Website : www.kalamlok.com

वर्ष - 09 अंक - 338

बक्सर, बुधवार 22 अप्रैल 2026

≺7

कलम लोक

पृष्ठ - 8
मूल्य 2 रू.

“ सच्चाई, ईमानदारी, सज्जनता और सौजन्य जैसे गुणों के बिना कोई मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता।

बांग्लादेश जाने की कर लो तैयारी, पाताल से निकाल उलटा लटकाएंगे; अमित शाह ने किसे सुनाया?

चांदीपुर (एजेंसी)।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनावों के लिए प्रचार का शोर मंगलवार (21 अप्रैल) को देर शाम थम गया। इससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने को दावा किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में रहने वाले गुंडों को छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी।

उन्होंने मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने का आग्रह किया और कहा कि केंद्रीय बल ऐसे उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की रिकॉर्ड 2,450 कंपनियां तैनात की हैं। इन 2450 कंपनियों में लगभग 2.5 लाख जवान शामिल हैं।

गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम से सटे पूर्व मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर में अपनी अंतिम चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को 'टा टा, गुडबाय' कहा। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, 'राज्य की बागडोर संभालने का उनका (ममता का) समय समाप्त हो गया है।' उन्होंने विश्वास जताया कि चार मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा सत्ता में आ आएगी।

शाह ने यह भी वादा किया कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर बांग्लादेश के साथ बंगाल की सीमा को सील कर दिया जाएगा।

उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश वापस जाने की तैयारी करें। उन्होंने कट मनी पर कहा कि बंगाल की जनता इससे परेशान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही इसके सिंडिकेट वालों को उलटा लटकाएंगे। वो चाहे कहीं भी छुपे हों, पाताल से निकालकर जेल में डाल देंगे।

भाइपो बंगाल का भावी मुख्यमंत्री नहीं होगा

शाह ने कहा, 'भाइपो (भतीजा अभिषेक बनर्जी) बंगाल का भावी मुख्यमंत्री नहीं होगा। उन्होंने चार मई के बाद राज्य छोड़ने के लिए अपना टिकट पहले ही खरीद लिया है।' उन्होंने 'भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने वाले तृणमूल के गुंडों को छिपने की जगह ढूंढने की चेतावनी दी। शाह ने कहा, 'चार मई को जब नतीजे घोषित होंगे, तो उनके पास भागने की कोई जगह नहीं बचेगी।' केंद्रीय गृह मंत्री ने वादा किया कि बंगाल में सत्ता में आने पर भाजपा चांदीपुर में पान के औषधीय गुणों का अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगी।

45 दिनों के अंदर सीमा सील करेंगे

शाह ने यह भी कहा कि सरकार बनने के 45 दिनों के अंदर सीमा सील करेंगे। इतना ही नहीं बंगाल से 4 शादी, तीन तलाक खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि ष्टष्ट लाकर ये सब खत्म करेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि बंगाल में बीजेपी आने वाली है, इसलिए ममता के गुंडे 23 को घर से न निकलें। शाह ने लोगों से निडर होकर मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा, 'कोई भी हमारे मतदाताओं को धमका नहीं सकता। आयोग ने पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों को तैनात किया है, जो राज्य के हर कोने में फैले हुए हैं।' केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि ममता बनर्जी की अपने भतीजे अभिषेक को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की आकांक्षा कभी पूरी नहीं होगी। मंच पर भाजपा के नंदीग्राम से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे।

संघर्ष विराम पर ईरान की ओर से जवाब न मिलने के कारण ट्रंप प्रशासन ने उठाया कदम

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा स्थगित, ईरान की चुप्पी के बाद ट्रंप प्रशासन का फैसला

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान की प्रस्तावित यात्रा को टाल दिया गया है। अब जेडी वेंस ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यह फैसला तब लिया, जब ईरान ने शांति वार्ता की शर्तों को ठुकरा दिया है। इससे मध्यस्थ पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, जो चंद घंटे पहले तक बुधवार को अमेरिका-ईरान शांति वार्ता आयोजित कराने का दावा कर रहा था।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, हालात की सीधी जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, जेडी वेंस की इस्लामाबाद की यह यात्रा रद्द नहीं की गई है, बल्कि फिलहाल इसे स्थगित रखा गया है। इसे बहुत कम समय के नोटिस पर फिर से शुरू किया जा सकता है। जेडी वेंस के मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जाने की उम्मीद थी, ताकि वे बुधवार को होने वाली बातचीत में शामिल हो सकें।

अगर ईरान के वार्ताकार इस तरह से जवाब देते हैं जिसे राष्ट्रपति ट्रंप स्वीकार्य मानते हैं, तो यह यात्रा किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती है। अमेरिकी अधिकारी एक स्पष्ट संकेत की भी तलाश में हैं कि ईरान के वार्ताकारों को किसी समझौते पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से अधिकार दिए गए हैं। वहीं, शांति वार्ता स्थगित होने के बाद अमेरिकी युद्ध विभाग पेंटागन सैन्य विकल्पों की समीक्षा कर रहा है, ताकि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तेहरान ईमानदारी से बातचीत नहीं कर रहा है, तो उन विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सके।

अमेरिका-ईरान में किन मुद्दों पर गतिरोध

अमेरिका ने हाल ही में ईरानियों को एक लिखित प्रस्ताव भेजा था, जिसका उद्देश्य समझौते के कुछ बुनियादी बिंदु तय करना था, जो आगे की विस्तृत बातचीत का आधार बन सकें। बातचीत में मुख्य अड़चनें अभी भी वही मुद्दे हैं, जिन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय से पश्चिमी वार्ताकारों को परेशान कर रखा है। इनमें ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का दायरा और उसके पास जमा संवर्धित यूरेनियम का भविष्य प्रमुख हैं।

चेन्नई में खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कहा, बाद में दी सफाई

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और उन्हें आतंकवादी कहा. खड़गे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी विपक्ष को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक दलों और लोगों को आतंकित कर रहे हैं.

हालांकि, जब पत्रकारों ने उन्हें टोका, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब था कि प्रधानमंत्री देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को आतंकित कर रहे हैं. खड़गे ने कहा, वह लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं. मैंने कभी नहीं कहा कि वह (असल में) आतंकवादी हैं. वह अपनी शक्ति और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को गाली दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी ऑफिस का विस्तार बन गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव प्रचार अभियान के आखिरी चरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक लोगों को डराने-धमकाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले सम्राट चौधरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। । बिहार का सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई. वैसे तो ये शिष्टाचार मुलाकात थी लेकिन इसके बेहद अहम मायने हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि विकास योजनाओं से लेकर कैबिनेट विस्तार तक पर उनके बीच बातचीत हुई है. पीएम मोदी से भेंट के बाद सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीर साझा की है. साथ ही लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की. विकसित भारत और समृद्ध बिहार के विजन पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ.

फौरन खाली कर दें पर्यटक स्थल, तट और रिसॉर्ट

चुनाव आयोग ने बंगाल में पहली बार दिए ऐसे आदेश, कब तक रहेगा लागू?

कोलकाता (एजेंसी)।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने पहली बार एक खास किस्म का आदेश जारी किया है। इसके तहत आयोग ने बंगाल के पर्यटक स्थलों को खाली करने का आदेश दिया है। आयोग के निर्देश के मुताबिक, पर्यटकों और गैर-निवासियों को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के लोकप्रिय तटीय स्थलों यानी दीघा, मंदारमणि, ताजपुर, उदयपुर और शंकरपुर को खाली करने का आदेश दिया है। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में होटलों को भी निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके कमरों में कोई भी ऐसा व्यक्ति न ठहरे जो उस जिले का निवासी न हो। आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था मंगलवार शाम 6 बजे से लेकर 23 अप्रैल को मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।

पूर्वी मेदिनीपुर का तटीय इलाका साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है और यह पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। अब आयोग के इस आदेश से, इस पूरे क्षेत्र में 48 घंटों के लिए पर्यटकों की गतिविधियाँ प्रभावी रूप से बंद हो जाएंग। यह एक असाधारण रूप से व्यापक प्रतिबंध है जो केवल मतदान से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित न रहकर अब आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्र को भी प्रभावित करने वाला है।

प्रचारकों के रुकने पर भी पाबंदी

चुनाव निकाय के इस अभूतपूर्व आदेश में राजनीतिक दलों के प्रचारकों को भी इस अवधि के दौरान क्षेत्र में रुकने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर उसे 'भारतीय न्याय संहिता' की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा; इस धारा के तहत किसी लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना करने पर 6 से 12 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

अपनी तरह का पहला आदेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'वास्तविक पर्यटकों को भी इलाका खाली करने के लिए कहने के पीछे का तर्क यह आशंका है कि कुछ बाहरी लोग, जो अशांति फैलाने का इरादा रखते हैं, पर्यटन की आड़ में जिले में प्रवेश कर सकते हैं और मतदान के दौरान उपद्रव भड़का सकते हैं।' पर्यटकों को इलाका खाली करने का यह आदेश, ECI द्वारा किसी विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किया गया अपनी तरह का पहला आदेश है।

पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु में थमा चुनाव प्रचार, 23 अप्रैल को मतदान

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के लिए मतदान होने हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

चुनाव प्रचार थमने से पहले दोनों राज्यों में शीर्ष नेताओं और उम्मीदवारों ने समर्थकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं, चुनाव प्रचार थमने के बाद अब कोई भी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा या रैली नहीं कर सकेगा। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो यहां इस बार दो चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाना है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में कुल 1,478 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं, तीन करोड़ 60 लाख 77 हजार 171 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इन मतदाताओं में एक करोड़ 75 लाख 77 हजार 210 महिलाएं अपने मत का इस्तेमाल करेंगी। आरक्षण को लेकर बने माहौल के बीच इस बार पश्चिम बंगाल में महिलाओं की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। बंगाल में पहले चरण में जहां मतदान होने हैं, उनमें उत्तर बंगाल के आठ, दक्षिण बंगाल के तीन व जंगलमहल अंचल के पांच जिले शामिल हैं।

4 मई को तृणमूल सरकार का जाना तय : अनुराग ठाकुर

कोलकाता (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कोलकाता में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि इस बार चुनाव ममता बनर्जी बनाम जनता के बीच है। उन्होंने कहा कि जब जनता चुनाव अपने हाथ में लेती है, तो परिणाम एकतरफा होता है। राज्य भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उनके साथ हर्षवर्धन श्रिंगला भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य भाजपा के मुख्य प्रवक्ता देवजीत सरकार ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य सरकार केवल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सरकार बनकर रह गई और जनता के हितों की अनदेखी हुई।

दिल्ली में टारगेट किलिंग और ग्रेनेड हमलों की योजना बना रहे दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कथित प्रॉक्सी शहजाद भट्टी से जुड़े एक खतरनाक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस साजिश में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली-एनसीआर में फायरिंग, ग्रेनेड हमले और टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय राजवीर और 19 वर्षीय विवेक बंजारा के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र के रहने वाले हैं.

पुलिस के अनुसार, दोनों को सोशल मीडिया के जरिए 'राणा भाई' नामक व्यक्ति ने संपर्क किया, जो शहजाद भट्टी का करीबी सहयोगी है. इसके बाद दोनों सीधे भट्टी के संपर्क में आ गए और उसके निर्देश पर काम करने लगे. जांच में सामने आया कि पाकिस्तान में बैठा शहजाद भट्टी भारत में आपराधिक नेटवर्क के जरिए बड़ी साजिश रच रहा था. वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को जोड़कर उन्हें पैसे और हथियार मुहैया कराता था, ताकि दिल्ली-एनसीआर में दहशत फैलाने वाली घटनाओं को अंजाम दिया जा सके. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इनपुट मिला था कि यह मॉड्यूल दिल्ली में किसी बड़े होटल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है. इसी आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. सबसे पहले विवेक बंजारा को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी राजवीर को सराय काले खां इलाके से दबोचा गया.

ऐक्शन में सम्राट सरकार

हर महीने चार बार मेडिकल कॉलेज की चेकिंग, एक बार औचक निरीक्षण

पटना (एजेंसी)। बिहार सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती साख को बचाने और व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों का महीने में कम से कम चार बार नियमित निरीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने जा रहा है। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्तर से विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का दौरा करेंगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि महीने में होने वाले कुल चार निरीक्षणों में से एक औचक निरीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इन निरीक्षणों के दौरान टीम कई मुख्य बिंदुओं पर बारीकी से जांच करेगी। इसमें डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की समय पर उपस्थिति, मरीजों को अस्पताल से मुफ्त दवाओं की उपलब्धता, वार्डों और ऑपरेशन थिएटरों में साफ-सफाई का स्तर, और आपातकालीन वार्ड में मिलने वाली तुरंत सुविधाओं की स्थिति शामिल है। निरीक्षण के तुरंत बाद, यह टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट सीधे सरकार को सौंपेगी। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है।

4 बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ विकास की रफ्तार को तेज करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सिंचाई और पथ निर्माण विभाग की दो-दो बड़ी परियोजनाओं पर विशेष फोकस रहा। मुख्य सचिव ने उत्तर कोयल जलाशय योजना के अवशेष कार्यों की बारीकी से समीक्षा की और मंडई वीयर सहित इससे जुड़ी मुख्य नहर प्रणालियों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं, पथ निर्माण के क्षेत्र में बख्तियारपुर से ताजपुर के बीच गंगा नदी पर बन रहे ग्रीनफील्ड महासेतु के कार्यों का जायजा लिया गया, जो उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी को काफी कम कर देगा। इसके अलावा, भागलपुर और खगड़िया के बीच निर्माणाधीन सुल्तानगंज-अगुवानी घाट फोर लेन पुल की प्रगति पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा करने का सख्त निर्देश दिया।

देश छोड़कर भागे नहीं जा रहे...

पवन खेड़ा की अर्जी पर सिंघवी और एजी में तीन घंटे तीखी भिड़ंत

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार (21 अप्रैल) को गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि कांग्रेस नेता के देश से भागने का कोई खतरा नहीं है। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह याचिका असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दर्ज की गई एक FIR के संबंध में है। दरअसल, पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि उनके पास कई पासपोर्ट हैं। इसी के खिलाफ आपराधिक FIR दर्ज की गई है। उसी मामले में खेड़ा ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है।

जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की तीन घंटे से ज़्यादा समय तक गरमागरम दलीलें सुनने के बाद अपना अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कांग्रेस नेता के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री सरमा की टिप्पणी, खासकर राज्य में विधानसभा चुनावों के संदर्भ में राजनीतिक बदले की भावना की ओर इशारा करती है।

सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता के देश से भागने का कोई खतरा नहीं है और उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके खिलाफ असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने खेड़ा को कोई भी राहत देने का सख्त विरोध करते हुए कहा कि यह कोई साधारण मानहानि का मामला नहीं है, क्योंकि यह मामला दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़ा है। सैकिया ने बताया कि मुख्य अपराध धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े हैं।

बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, मल्टी पोस्ट ईवीएम इसी महीने आएंगी; 24 घंटे होगी निगरानी

पटना (संवाददाता)। बिहार के इस साल के अंत में होने वाले पंचायत आम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयार तेज कर दी है। पंचायत चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा एस-3 मॉडल की मल्टी पोस्ट ईवीएम खरीदी जा रही हैं। ये ईवीएम इसी महीने (अप्रैल) सभी जिलों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। फिर इन्हें कड़ी निगरानी में रखा जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद मंगलवार को सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि मल्टी पोस्ट ईवीएम का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उनकी 24 घंटे (24×7) सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाए। चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर ससमय आयोग को भेज दी जाए। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए आयोग द्वारा मल्टी पोस्ट S-3 मॉडल ईवीएम की 32200 कंट्रोल यूनिट एवं 193200 बैलेट यूनिट की खरीद की जा रही है।

आयुक्त ने सभी डीएम को निर्देश दिया कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार वार्ड वार जनसंख्या का सत्यापन कर वेबसाइट पर प्रविष्टि करें। प्रपत्र-एक (फॉर्म 1) में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे, इसके लिए अनुमंडल स्तर पर दोहरी जांच अनिवार्य रूप से की जाए। संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर निर्धारित तारीख से पहले प्रपत्र-1 का प्रकाशन करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने फॉर्म-1 पर प्राप्त दावा और आपत्तियों का निस्तारण नियमावली की समय सीमा में निष्पादित करने का भी निर्देश है। इस अवसर पर आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा, संयुक्त निर्वाचन आयुक्त शंभु कुमार एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

मल्टी पोस्ट ईवीएम, सामान्य वोटिंग मशीन से थोड़ी अलग होती है। इसमें कंट्रोल यूनिट तो एक ही होती है, जबकि बैलेट यूनिट एक से अधिक होती है। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के दो-दो यानी कुल 6 पदों पर एक साथ मतदान होगा। इसलिए हर बूथ पर 6 बैलेट यूनिट होगी। इसमें मतदाता मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य आदि को अलग-अलग बैलेट यूनिट में वोट कर सकेंगे। हालांकि, इनकी कंट्रोल यूनिट एक ही होगी। यानी कि सभी 6 बैलेट यूनिट का नियंत्रण वहां पर लगी एक ही कंट्रोल यूनिट से किया जाएगा।

नवंबर-दिसंबर में पंचायत चुनाव

बिहार में पंचायत चुनाव नवंबर और दिसंबर 2026 में होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग इसकी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। पिछले दिनों आयोग ने सभी जिलों में डीएम को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) नियुक्त कर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी थी। वहीं, 27 अप्रैल तक सभी पंचायतों में प्रारूप का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद वोटर लिस्ट का काम शुरू हो जाएगा।

एयरपोर्ट पर बंगाल नंबर की गाड़ी से लेने आए तो मुख्य सचिव भड़के, बिना लंच किए पटना लौटे

किशनगंज (संवाददाता)। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के किशनगंज दौरे में हुए एक वाकये से प्रशासनिक हलके में हलचल मच गई है। मुख्य सचिव जैसे ही मंगलवार को किशनगंज एयरपोर्ट पर उतरे, तो व्यवस्था देखकर स्थानीय प्रशासन से नाराज हो गए। जिला प्रशासन ने उनके लिए पश्चिम बंगाल के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी उपलब्ध कराई थी। बंगाल नंबर की गाड़ी देखते ही प्रत्यय अमृत भड़क गए और उसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया। फिर वह दूसरी गाड़ी में बैठकर समाहरणालय गए। वहां डीजीपी विनय कुमार के साथ अधिकारियों की बैठक ली और बिना लंच किए ही पटना लौट गए।

मुख्य सचिव की नाराजगी प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रत्यय अमृत ने जब एयरपोर्ट पर बंगाल नंबर की गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया, तब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वे पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त की सरकारी गाड़ी से किशनगंज समाहरणालय पहुंचे। वहां उन्होंने पूर्व से निर्धारित बैठक में भाग लिया और विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा की। हालांकि, बैठक समाप्त होने के बाद भी मुख्य सचिव की नाराजगी शांत नहीं हुई। बताया जा रहा है कि किशनगंज में बैठक के बाद प्रत्यय अमृत के भोजन ग्रहण करने का भी कार्यक्रम था। मगर बिना लंच किए ही वे तुरंत पटना के लिए रवाना हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अधिकारी वर्ग में इसे लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जबकि जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। किशनगंज में सोमवार को सीमांचल में सुरक्षा के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इसमें बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी पहुंचे। साथ ही किशनगंज और अररिया जिले के डीएम, एसपी समेत अन्य वरीय पदाधिकारी और सशस्त्र सीमा बल (एएसएसबी) के अफसर भी मौजूद रहे।

निशांत कुमार की बिहार यात्रा की तारीख आई, पिता नीतीश की तरह चंपारण से करेंगे आगाज

पटना (संवाददाता)। जनता दल यूनाइटेड के नेता निशांत कुमार की बिहार यात्रा की तारीख आ गई है। निशांत आगामी 3 मई को अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। वह अपने पिता नीतीश कुमार की तरह पश्चिम चंपारण से ही बिहार यात्रा का आगाज करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश भी अक्सर चंपारण से ही अपनी सियासी यात्राओं की शुरुआत करते रहे हैं। आगामी यात्रा में नीतीश के बेटे निशांत बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे। पिछले महीने राजनीति में कदम रखने के तुरंत बाद ही उन्होंने यात्रा निकालने का फैसला कर लिया था।

जदयू नेता निशांत कुमार ने मंगलवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी बिहार यात्रा 3 मई से शुरू होने की संभावना है। पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता इसकी तैयारी में जुटे हैं। हालांकि, निशांत की पहली सियासी यात्रा का पूरा कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, जदयू के नेता एवं कार्यकर्ता, सब लोग मिलकर तय करके बताएंगे। निशांत की पहली बिहार यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होने वाली है। चंपारण को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की कर्मभूमि कहा जाता है। उन्होंने बेतिया के भितिहरवा में आश्रम बनाया था। अंग्रेजों द्वारा किसानों पर किए जा रहे शोषण के खिलाफ सत्याग्रह किया था। इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है।

नीतीश कुमार लगभग दो दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई यात्राएं निकालीं। अधिकतर यात्राओं की शुरुआत वह चंपारण से ही करते रहे हैं।

एक्सीडेंट के 24 घंटे के अंदर मालिक को गाड़ी लौटा देगी पुलिस, मुख्यालय से आदेश जारी

पटना (संवाददाता)। बिहार में सड़क हादसों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को छोड़ने में अनावश्यक देरी अब नहीं चलेगी। पुलिस को सड़क दुर्घटना के बाद 24 घंटे के अंदर गाड़ी संबंधित वाहन मालिक को लौटाना होगा। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को आदेश जारी किया है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्तर के कंट्रोल रूम का वाट्सएप नंबर 9031829356 भी जारी किया गया है। इस नंबर के माध्यम से एक निर्धारित फॉर्मेट में सूचना देने के लिए गाड़ी मालिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने मंगलवार को पत्र जारी कर कहा है कि थाना स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मुक्त करने में अनावश्यक विलंब की शिकायत मिलती रही है। सभी एसपी को मोटरयान अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा गया है कि दुर्घटना के बाद गाड़ी कहां ले जाई जा रही है, इसकी जानकारी मालिक या ड्राइवर को देनी होगी।

गाड़ी की जांच एवं संबंधित पोर्टल पर प्रविष्टि के बाद 24 घंटे के अंदर संबंधित वाहन को वापस लौटा दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि पुलिस या अनुसंधान पदाधिकारी को गाड़ी छोड़ने से पहले दो गवाहों की उपस्थिति में पंचनामा बनाना होगा। इसके साथ ही प्रत्येक एंगल से मुक्त की जा रही गाड़ी की तस्वीर भी लेनी होगी। इस पर पीड़ित पक्ष और अभियुक्त दोनों का हस्ताक्षर लेना अनिवार्य होगा। पुलिस मुख्यालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आर्म्स एक्ट, नारकोटिक्स, विस्फोटक, अवैध शराब, रंगदारी, डकैती, लूट, दुष्कर्म, हत्या मामले में जब्त गाड़ी को 24 घंटे में छोड़ने का आदेश प्रभावी नहीं होगा। इसके लिए कोर्ट का आदेश जरूरी होगा।

पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी, बंगाल चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट का प्रचार करने पहुंचे थे

पूर्णिया (संवाददाता)। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मंगलवार को तबीयत बिगड़ गई। वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट का प्रचार करने पहुंचे थे। ।बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी में प्रचार करने की वजह से उनकी हालत थोड़ी खराब हो गई। इसके बाद डॉक्टर की निगरानी में सांसद का इलाज किया गया। इलाज के बाद उनकी तबीयत में सुधार आ गया है। चुनाव प्रचार खत्म कर वे शाम को पूर्णिया के लिए रवाना भी हो गए।

पूर्णिया सांसद के कार्यालय सचिव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान भीषण गर्मी की वजह से पप्पू यादव की तबीयत दोपहर में खराब हो गई। उन्हें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा गया। वहीं, उनके प्रवक्ता ने मंगलवार शाम को बताया कि सांसद अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। वह मालदा से पूर्णिया लौट रहे हैं।

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को इंग्लिश बाजार से कांग्रेस प्रत्याशी मसूद आलम और हरिशचंद्रपुर सीट से मुश्ताक आलम के समर्थन में रोड शो कर वोट मांगे। बंगाल का यह जिला बिहार से सटा हुआ है। पप्पू यादव ने कहा कि मालदा, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। भाजपा यहां साजिश कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाएगी।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। मालदा जिले में पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है। यहां चुनाव प्रचार का मंगलवार को आखिरी दिन था। वहीं राज्य में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। दोनों चरणों की मतगणना 4 मई को होगी।

पप्पू यादव के बयान पर बवाल, महिला आयोग से नोटिस

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के हाल ही में महिला नेत्रियों को लेकर दिए एक बयान पर विवाद हो गया है। सांसद ने कहा कि नेताओं के कमरे में गए बगैर 90 प्रतिशत महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि राजनेता सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण करते हैं। पप्पू यादव की इस टिप्पणी पर सियासी घमासान मच गया। बिहार राज्य महिला आयोग ने इस पर आपत्ति जताते हुए उन्हें नोटिस भेज दिया। आयोग ने सांसद से 3 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही भाजपा, जदयू समेत सत्ताधारी दलों ने उनके बयान पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव से सार्वजनिक माफी की मांग की है।

सिलीगुड़ी से पटना जा रही बस की मिनी ट्रक से टक्कर, स्लीपर से नीचे गिर गए यात्री

अररिया (संवाददाता)। बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से पटना जा रही यात्री बस ने एक मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर से मिनी ट्रक के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, बस में सवार लगभग आधा दर्जन यात्री भी घायल हुए हैं। स्लीपर में सो रहे यात्री अचानक हुई टक्कर से नीचे गिर गए और उन्हें चोट लग गई। इस हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। ट्रक का ड्राइवर भी केबिन में फंस गया। गैस कटर की मदद से उसे बाहर निकालना पड़ा।यह हादसा फारबिसगंज के पटना बस स्टैंड स्थित आईटीआई के सामने अवैध कट के पास सोमवार देर रात को हुआ। मिनी ट्रक कोलकाता से बेतिया की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसकी स्पीड तेज थी। इसी दौरान राज नामक एक यात्री बस ढाबे से निकलकर सर्विस रोड के जरिए अवैध कट को पार करते हुए बस स्टैंड में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। तभी बस ने तेज रफ्तार मिनी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी।

पेयजल आपूर्ति, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर उपमुख्यमंत्री साव सख्त

अगले एक वर्ष में पेयजल समस्याओं के स्थायी समाधान के निर्देश, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर कड़ाई बरतने को कहा

रायपुर।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में दिनभर चली बैठक में शहरों में पेयजल आपूर्ति की समस्याओं, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर नाराजगी जाहिर करते हुए इनके निराकरण के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने धमतरी में पेयजल योजना के काम में लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने तथा ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए।

नगर निगमों और नगर पालिकाओं की आज दो अलग-अलग हुई समीक्षा बैठकों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक श्री आर. एक्का और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय सहित सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वरिष्ठ अभियंता एवं नगरीय प्रशासन विभाग के पांचों संभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक भी बैठक में मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में नगर निगमों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को शहरों की जरूरत के मुताबिक कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकायों की व्यवस्था और छवि सुधारने सक्रियता व गंभीरता से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि नगर निगम ऐसा काम करें जिससे राज्य की नगर पालिकाएं प्रेरणा ले सकें और नगर पालिका इस तरह से काम करें जिनसे नगर पंचायतें प्रेरित हो सकें। उन्होंने निकायों के अभियंताओं से कहा कि काम की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें नहीं आना चाहिए। सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों, इस पर विशेष ध्यान दें।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने पेयजल आपूर्ति की लगातार आ रही शिकायतों पर नाखुशी और नाराजगी जाहिर करते हुए अगले वर्ष तक सभी नगर निगमों में इसके स्थाई समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरों में केवल बजट खर्च करने के उद्देश्य से काम न करें, बल्कि समस्याओं का स्थाई समाधान करें। पेयजल समस्या की शिकायतों पर जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगामी 31 मई तक सभी नगर निगमों में बड़े नाला-नालियों और ड्रेनेज की सफाई के काम पूर्ण करने के साथ ही बरसात में जल भराव रोकने जरूरी उपाय करने को कहा। जून के पहले सप्ताह में राज्य स्तरीय टीम नगर निगमों में इसका भौतिक निरीक्षण करेंगी। कार्य संतोषजनक न मिलने पर स्वास्थ्य अधिकारी और इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। श्री साव ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अपूर्ण आवासों को सितम्बर-2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अप्रारंभ आवासों के निर्माण एक माह के भीतर हर हाल में शुरू करने के साथ ही मार्च-2026 में स्वीकृत सभी आवासों को वर्षा ऋतु के पहले प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत निर्धारित 18 माह की अवधि में निर्माण पूर्ण करने वाले हितग्राहियों के प्रस्ताव अविलंब विभाग को भेजने के निर्देश दिए, ताकि ऐसे हितग्राहियों को मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की 32 हजार 850 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा सके। श्री साव ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाने बैंकों से बात कर ऋण स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरों में भूजल को रिचार्ज करने के लिए डीएमएफ, सीएसआर और जन सहयोग से अधिक से अधिक संख्या में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य कराने को कहा। श्री साव ने शहरों को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाने के मिशन में वर्तमान समय की जरूरतों और तकनीकों के साथ नई कार्य पद्धति अपनाने के निर्देश निकायों के अधिकारियों को दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उप सचिव श्री भागवत जायसवाल, अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज दो सत्रों में मैराथन बैठकों में नगरीय निकायों में राजस्व वसूली, विद्युत देयकों के भुगतान, वेतन भुगतान, अधोसंरचना विकास व 15वें वित्त आयोग के कार्यों, नालंदा परिसरों, नगरोत्थान योजना, जलप्रदाय योजनाओं, आपदा प्रबंधन, गोधाम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, आई-गॉट (I-got) कर्मयोगी तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों की समीक्षा की। वे 21 अप्रैल को दिनभर नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

4.19 लाख से अधिक जांच, 4272 मरीजों को मिला विशेषज्ञ उपचार- मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान से सुदूर अंचलों तक पहुंच रही सशक्त स्वास्थ्य सेवाएं

रायपुर।

बस्तर संभाग के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने की दिशा में संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान सकारात्मक परिणामों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा गांव-गांव पहुंचकर अब तक 4,19,898 से अधिक नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण (स्क्रीनिंग) किया जा चुका है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। अभियान के दौरान चिन्हित मरीजों को तत्काल नि:शुल्क जांच, दवा एवं उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही गंभीर एवं जटिल मामलों में प्रभावी रेफरल व्यवस्था के माध्यम से अब तक 4,272 मरीजों को उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर कर विशेषज्ञ उपचार सुनिश्चित किया गया है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों एवं सुपर स्पेशियलिटी संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित कर एक सुदृढ़ स्वास्थ्य तंत्र विकसित किया गया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एवं नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से विशेष रूप से पहुंचविहीन क्षेत्रों तक सेवाएं प्रभावी रूप से पहुंचाई जा रही हैं। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल (आभा) तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। साथ ही, यह पहल रोगों की समय पर पहचान और प्रभावी उपचार में भी सहायक सिद्ध हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत लगातार गांव-गांव पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे और शत-प्रतिशत स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। चिन्हित मरीजों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के साथ बेहतर स्वास्थ्य परिणाम हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। यह अभियान बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाला साबित हो रहा है। राज्य शासन की प्रतिबद्धता और स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों से अभियान को निरंतर बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, जो बस्तर के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बस्तर के लिए खुले वैश्विक द्वार, 4 घंटे में पूरा होगा समंदर तक का सफर

रायपुर।

बस्तर की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर एक क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा यह 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर न केवल दूरियों को कम करेगा, बल्कि बस्तर के स्थानीय उत्पादों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों तक पहुँच प्रदान कर लैंड-लॉक्ड क्षेत्र की बाधाओं को समाप्त करेगा।

दुर्गम घाटों से मुक्ति और समय की बड़ी बचतवर्तमान में जगलपुर से विशाखापट्टनम की यात्रा ओडिशा के कोरापुट और जयपुर के कठिन घाटों से होकर गुजरती है, जिसमें 7 से 9 घंटे का समय लगता है। भारी वाहनों के लिए यह मार्ग न केवल थकाऊ है, बल्कि डीजल की खपत और मेंटेनेंस के लिहाज से भी खर्चीला है। नया कॉरिडोर इस यात्रा को मात्र 3.5 से 4 घंटे में समेट देगा। सीधा और घाट-मुक्त रास्ता होने के कारण वाहनों का परिचालन खर्च काफी कम हो जाएगा, जिससे परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।नबरंगपुर इंटरचेंज: बस्तर का प्रवेश द्वाररायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर और कोंडागांव जिलों से गुजर रहा है। जगदलपुर मुख्यालय को इस कॉरिडोर से जोड़ने के लिए ओडिशा के नबरंगपुर का दासपुर इंटरचेंज महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। जगदलपुर का ट्रैफिक मात्र 50-60 किमी का सफर तय कर नबरंगपुर इंटरचेंज के माध्यम से रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल हो सकेगा, जिससे बस्तर सीधे विशाखापट्टनम पोर्ट और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ जाएगा। बस्तरिया ब्रांड का अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेशइस कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बस्तर की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब बस्तर की अरेबिका कॉफी, जैविक इमली, महुआ उत्पाद और प्रसिद्ध ढोकरा शिल्प को विशाखापट्टनम पोर्ट तक पहुँचाना सुगम होगा। कम लॉजिस्टिक लागत के कारण ये उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय किसानों, संग्रहकर्ताओं और शिल्पकारों को उनकी उपज का बेहतर अंतरराष्ट्रीय मूल्य मिल सकेगा।सामाजिक और आर्थिक उत्थानबस्तर, कांकेर और कोंडागांव जैसे आकांक्षी जिलों को इस परियोजना से सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाएं इन सुदूर क्षेत्रों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगी। इस राजमार्ग के माध्यम से बस्तर का कृषि उत्पाद और इस्पात सीधे रायपुर, दुर्ग-भिलाई और विशाखापट्टनम जैसे औद्योगिक केंद्रों से जुड़ जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी, प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर में हजारों नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह कॉरिडोर बस्तर में औद्योगिक विकास की एक नई लहर लाने के लिए तैयार है। औद्योगिक और खनिज विकासबस्तर क्षेत्र लौह अयस्क और अन्य खनिजों से समृद्ध है।

कृषि मंत्री नेताम ने मिट्टी एवं बीजों की पूजा की और ट्रैक्टर चलाकर बीजों की बुआई की

कृषि विश्वविद्यालय में मनाया गया अक्ती तिहार, प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं अनुसंधान प्रक्षेत्रों में भी हुआ अक्ती तिहार का आयोजन

रायपुर।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज अक्ती तिहार के अवसर पर ट्रेक्टर चलाकर सीड ड्रील से धान बीज का रोपण किया और बाड़ी में सब्जियों के बीजों की बुआई की। कृषि मंत्री ने अच्छी फसल के लिए धरती माता से प्रार्थना की और गौ माता को चारा भी खिलाया। उन्होंने इस अवसर पर किसानों को उन्नत बीज, खाद एवं कृषि यंत्र भी वितरित किये। अक्ती तिहार का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त महाविद्यालयों, अनुसंधान प्रक्षेत्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में भी किया गया।

मंत्री श्री नेताम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अक्षय तृतीया के अवसर पर "अक्ती तिहार" के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। मंत्री श्री नेताम ने इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र में माटी पूजन, बीज पूजन तथा ठाकुर देवता की पूजा अर्चना कर खेती किसानी के नए कार्यों की शुरूआत की। समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि हमें कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करते हुए जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों एवं जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है जो मिट्टी और पर्यावरण की सेहत के लिए अधिक सुरक्षित हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करने के लिए सुनियोजित रणनीति बनाई गई है जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी तकनीकी सहयोगी के रूप में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि अक्ती तिहार धरती के प्रति अपनी कृतिज्ञता प्रकट करने का त्यौहार है। हमें सोचना चाहिए कि प्रकृति से हम जितना ले रहे हैं उसके बदले में धरती को क्या वापस कर रहे हैं। अक्ती तिहार के अवसर पर खेती किसानी का कार्य शुरू करने के पहले हम धरती माता से प्रार्थना कर उनसे अनुमति लेते हैं तब हल चलाते हैं। धरती माता को जो क्षति होती है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं।

श्री नेताम ने कार्यक्रम में ड्रोन का संचालन करने वाली ड्रोन दीदी श्रीमती फुलेश्वरी निषाद को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि एक घरेलू ग्रामीण महिला श्रीमती निषाद ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर ड्रोन दीदी के रूप में लोगों की सेवा कर रहीं हैं, यह प्रशंसनीय है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ती के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन हम धरती एवं बीजों की पूजा करते हैं तथा खेती किसानी के कार्य की शुरूआत करते हैं। डॉ. चंदेल ने कहा कि पिछले चार-पांच वर्षों से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अक्ती तिहार का भव्य एवं वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। आज कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों में भी अक्ती तिहार का आयोजन किया जा रहा है। किसानों के लिए नवीन बीज बुआई तकनीकी एवं कृषि में ड्रोन का उपयोग तकनीक का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र रायपुर द्वारा 'रासायनिक उर्वरकों का विकल्प' विषय पर कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा किसानों को रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर विभिन्न जैव उर्वरक एवं जैविक खाद के उपयोग की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि नील हरित काई, अजोला, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, फॉस्फोरस स्थिरीकरण बैक्टीरिया जैसे जैव उर्वरकों तथा हरी खाद के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की कमी पूरी की जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को नील हरित काई तथा अजोला खाद के निर्माण का प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया गया। समारोह में संचालक कृषि श्री राहुल देव, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री महेन्द्र सिंह सवन्नी, छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के एमडी श्री अजय अग्रवाल, कृषि विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. कपिल देव दीपक, संचालक प्रक्षेत्र डॉ. एस.एस. टूटेजा, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय डॉ. अजय वर्मा, अपर संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री जी.के. पीढ़िया सहित विभिन्न विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक कृषि वैज्ञानिक तथा बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

चुनाव आयोग ने ममता की भबानीपुर समेत 55 सीटों को घोषित किया संवेदनशील, जानें क्यों किया ऐसा?

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में धनबल के भारी इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया है। आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हाई-प्रोफाइल भबानीपुर सीट समेत राज्य की 55 विधानसभा सीटों को खर्च के लिहाज से 'संवेदनशील' घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग को डर है कि इन सीटों पर उम्मीदवार चुनाव प्रचार में तय सीमा से कहीं ज्यादा पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं। उम्मीदवारों के खर्चों पर पैनी नजर रखने और किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए आयोग ने राज्य में 100 विशेष पर्यवेक्षकों की फौज उतार दी है। देश के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार है जब चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों की तैनाती की है।

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध कैश, शराब, मादक पदार्थ और मुफ्त बांटी जाने वाली सामग्रियों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है और इनकी पकड़ लगातार बढ़ रही है। अवैध सामग्री की जब्ती के मामले में तमिलनाडु के बाद बंगाल पूरे देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब तक सभी चुनावी राज्यों को मिलाकर कुल 1,281 करोड़ रुपये की संदिग्ध खेप पकड़ी जा चुकी है। इसमें 105 करोड़ रुपये के कीमती जवाहरात और 178 करोड़ रुपये का ऐसा सामान शामिल है, जिसे मतदाताओं के बीच फ्री में बांटा जाना था। हैरानी की बात यह है कि अकेले पश्चिम बंगाल से ही 17 अप्रैल तक 430 करोड़ रुपये का अवैध सामान जब्त किया गया है। वोटरों को लुभाने के लिए अवैध तरीकों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए चुनाव आयोग ने सीमावर्ती इलाकों को खास रडार पर लिया है। संवेदनशील घोषित की गई सीटों में सीमांत क्षेत्र उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों से भारी मात्रा में कैश समेत कई अवैध चीजें बरामद की गई हैं। इसके अलावा 8 ऐसी विधानसभा सीटें भी हैं, जो सीधे बांग्लादेश की सीमा से लगती हैं। इन संवेदनशील सीटों में बिधाननगर, राजरहाट-न्यूटाउन, बारासात, मध्यमग्राम, भाटपारा, गैघाता और उत्तर बशीरहाट शामिल हैं, जहां चुनाव आयोग की टीम चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हुए है।

कोलकाता की 7 सीटें संवेदनशील, भबानीपुर में साख की लड़ाई

चुनाव आयोग की इस लिस्ट में राजधानी कोलकाता की 7 सीटों को भी इसी खास कैटेगरी में रखा गया है। इनमें से तीन सीटें उत्तर कोलकाता और चार सीटें दक्षिण कोलकाता क्षेत्र की हैं। सूची में सबसे चर्चित नाम भबानीपुर सीट का है, जो फिलहाल बंगाल की सबसे हाई-प्रोफाइल सीट बनी हुई है। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हरा दिया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने भबानीपुर से उपचुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इस बार भी दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की यह लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, जिसे देखते हुए आयोग कोई कोताही बरतना नहीं चाहता।

सीसीटीवी देख पुलिस भी हैरान

चोरी करने के बाद एसी चलाकर 6 घंटे तक सोता रहा चोर, फिर निकल गया

नवसारी (एजेंसी)। गुजरात में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने आम इंसान ही नहीं, बल्कि चोरों का भी हाल बेहाल कर दिया है। नवसारी से एक बेहद ही चौंकाने वाला और अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक चोर ने न सिर्फ एक ऑफिस में हाथ साफ किया, बल्कि तसल्ली से एसी चालू करके करीब छह घंटे तक चैन की नींद ली। सुबह होने से ठीक पहले वह वहां से रफूचक्कर हो गया। यह पूरी हैरान करने वाली वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे देखकर हर कोई दंग है।

चोरी की यह अजीबोगरीब घटना नवसारी के जुनाथाना इलाके में हुई है। जानकारी के मुताबिक, एक नकाबपोश चोर रात करीब 10:26 बजे ताला तोड़कर एक एडवरटाइजिंग (विज्ञापन) एजेंसी के ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने बड़े आराम से ऑफिस के दराज खंगाले और वहां रखे 60,000 रुपये नकद व 10 ग्राम चांदी पार कर दी। इस पूरी वारदात में चोर ने कुल 64,000 रुपये के माल पर हाथ साफ किया।

चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आमतौर पर तस्कर तुरंत भागने की फिराक में रहते हैं, लेकिन इस शातिर चोर का अंदाज बिल्कुल अलग था। बाहर की तपती गर्मी से बचने के लिए उसने भागने के बजाय ऑफिस का एयर कंडीशनर (AC) चालू कर दिया और कुर्सी पर बैठकर आराम करने लगा। ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि यह चोर रात 10:26 बजे घुसा था और तड़के 4:53 बजे तक ऑफिस के अंदर ही मौजूद रहा। करीब साढ़े छह घंटे तक एसी की ठंडी हवा का लुत्फ उठाने के बाद, सूरज निकलने से पहले वह शांति से वहां से निकल गया।

सुबह जब दुकान मालिक ने ऑफिस की हालत देखी और सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तो इस अनोखे वाकये को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पुलिस में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। चोर के इस बेखौफ और अजीब तरीके को देखकर पुलिस महकमा भी हैरान है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस शातिर चोर की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं और मामले की सरगर्मी से जांच की जा रही है।

आईएमडी ने जारी किया भयंकर हीटवेव का अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में जानलेवा गर्मी और लू को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। आने वाले कुछ दिन कई राज्यों के लिए भारी पड़ने वाले हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में 23 अप्रैल तक भीषण हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर सकते हैं। झारखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हीटवेव का अलर्ट है। वहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ओडिशा में भी हीटवेव की प्रबल संभावना बनी हुई है।

देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, 20 अप्रैल को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 39°C से 41°C के बीच और न्यूनतम तापमान 20°C से 22°C के आसपास रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में यह पारा और चढ़कर 40°C से 42°C के बीच बना रह सकता है। हालांकि, मौसम विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल दिल्ली में तकनीकी तौर पर लू चलने की संभावना नहीं है, लेकिन सामान्य से अधिक तापमान होने के चलते स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम लगातार बने हुए हैं। चिलचिलाती धूप का यह असर खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र में झुलसाने वाली गर्मी, चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल किए गए बंद

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि यहां पारा 43 डिग्री सेल्सियस को छू गया है। चिलचिलाती धूप और लू ने आम जनजीवन पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर लाल बत्ती होने के कारण लोगों को कड़ी धूप में लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, जिससे झुलसने का खतरा और परेशानी दोनों बढ़ गए थे। जनता की इस भारी समस्या को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने जिला यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक से गुहार लगाई। नागरिकों की इस जायज मांग पर तुरंत संज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस ने एक बेहद राहत भरा फैसला लिया है। अब दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक शहर के ट्रैफिक सिग्नल बंद रखे जाएंगे, ताकि दोपहिया वाहन चालकों और आम लोगों को तपती धूप में न रुकना पड़े। शाम 4 बजे के बाद सिग्नल व्यवस्था फिर से चालू कर दी जाएगी। यातायात पुलिस के इस मानवीय कदम की शहरवासी खूब सराहना कर रहे हैं।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बंदूक की नोक पर बच्चों को ले गया पिता फिर भी कस्टडी अवैध नहीं

इलाहाबाद (एजेंसी)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी के एक संवेदनशील मामले में ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने कानूनी जानकारों से लेकर आम लोगों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अदालत ने एक मां की ओर से दायर कस्टडी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि पिता ही नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक (नेचुरल गार्जियन) होता है। कोर्ट का कहना है कि जब तक किसी अदालती आदेश का सीधा उल्लंघन करके बच्चे को उसकी मां से जबरन अलग न किया जाए, तब तक पिता के पास बच्चों के रहने को अवैध कस्टडी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता महिला अंजलि देवी ने अपने पूर्व पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। महिला का दावा था कि साल 2022 में उसका पूर्व पति बंदूक की नोक पर उसके दो नाबालिग बच्चों को जबरन अपने साथ ले गया था और तब से उन्हें अवैध रूप से बंधक बनाकर अपने पास रखा हुआ है। महिला की दलील थी कि उसने बच्चों को वापस पाने के लिए कई जगह गुहार लगाई, लेकिन कोई असरदार कार्रवाई नहीं हुई।

कानून की नजर में पिता ही है बच्चों का 'प्राकृतिक संरक्षक'

इस अहम मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने 'तेजस्विनी गौड एवं अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी' केस के निर्णय का भी हवाला दिया। 10 अप्रैल को पारित अपने आदेश में अदालत ने आईपीसी की धारा 361 और अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम की धारा 4(2) की विस्तार से व्याख्या की। अदालत ने कहा कि कानून के अनुसार पिता को ही असल प्राकृतिक संरक्षक माना गया है। सिर्फ यह आरोप लगा देना कि पिता ने बच्चों को जबरदस्ती मां से छीना है, इसे अवैध कस्टडी साबित करने के लिए काफी नहीं है।

लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले से यह साफ कर दिया कि अगर पति-पत्नी के बीच अनबन है और अदालत का कोई आदेश मौजूद नहीं है, तो पिता का बच्चों को अपने साथ रखना गैरकानूनी नहीं ठहराया जा सकता, फिर चाहे बच्चों को जबरन ले जाने के आरोप ही क्यों न हों।

तालाब में डूबकर तीन सगे भाई बहनों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

कंधई (एजेंसी)। थाना क्षेत्र के शाल्हीपुर कंजास गांव में नहाते समय डूबकर तीन भाई बहनों की मौत हो गई। घटना के बाद जहां परिवार में कोहराम मच गया है वहीं पूरे गांव में मातम छा गया है। गांव निवासी विजय बहादुर यादव के तीन लड़के सबसे बड़ी बेटी 12 वर्ष, बड़ा बेटा 8 वर्ष और छोटा बेटा 5 वर्ष तीनों घर के सामने तालाब में नहाने गए थे। सोमवार को जब तीनों तालाब में घुसे तो बाहर ही नहीं निकले।

यह देख परिजनों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों ने तालाब मे घुसकर खोजबीन की। काी देर बाद तीनों को बाहर निकाला गया लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। इससे परिवार में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि विजय बहादुर की चार संतानें हैं।

आरएसएस प्रमुख ने लोगों से संस्कृत सीखने का आग्रह किया, कहा- यह राष्ट्र की आत्मा है

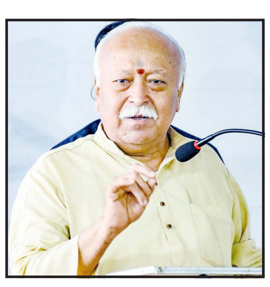

नई दिल्ली (एजेंसी)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने संस्कृत सीखने के महत्व पर जोर देते हुए इसे भारत की आत्मा और देश की सभ्यतागत निरंतरता का एक अनिवार्य तत्व बताया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में संस्कृत को आधुनिक संचार माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, संस्कृत एक भाषा है। फिर भी, यह मात्र एक भाषा नहीं है। भारत में, संस्कृत राष्ट्र की आत्मा है क्योंकि यह विचार, जीवन और संस्कृति की सबसे प्राचीन परंपरा है एक ऐसी परंपरा जो आज भी जीवंत है जो भारत में विद्यमान है।

उन्होंने भारत के दार्शनिक विचार को और विस्तार से समझाते हुए कहा, भारत का अस्तित्व मात्र एक भौगोलिक तथ्य नहीं है। यह महज एक राजनीतिक या आर्थिक इकाई नहीं है। भारत एक जीवंत परंपरा है, वह आधारशिला जिस पर जीवन की निरंतरता टिकी हुई है।

भाषा सीखने का सबसे आसान तरीका उसका नियमित रूप से उपयोग करना : भागवत

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि छात्र संस्कृत को एक कठिन भाषा मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह इतनी कठिन क्यों लगती है? वास्तव में, किसी भाषा को सीखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से नहीं, बल्कि बातचीत के माध्यम से है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाषा सीखने का सबसे आसान तरीका उसमें पूरी तरह डूब जाना और नियमित रूप से उसका उपयोग करना है।

अंतरिक्ष मौसम तक की मिलेगी सटीक जानकारी

पृथ्वी के छिपे हुए राज खोलेगा नासा का नया सैटेलाइट

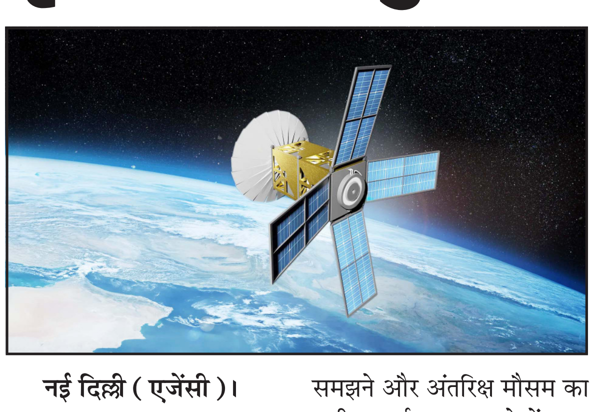

नई दिल्ली (एजेंसी)।

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सैटेलाइट को हाल ही में लॉन्च किया है, जो पृथ्वी से निकलने वाली प्राकृतिक और मानव-निर्मित रेडियो तरंगों का अध्ययन कर रहा है। यह मिशन वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण को बेहतर समझने और अंतरिक्ष मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगा।

कैनवास (क्लाइमेटोलॉजी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल वीएएफ वेव एक्टिविटी इन स्पेस) नामक यह क्यूबसैट 7 अप्रैल 2026 को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनोटौर IV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। यह अमेरिकी रक्षा विभाग के स्पेस टेस्ट प्रोग्राम एस29ए (एसटीपी-एस29ए) मिशन का हिस्सा रहा। वहीं, नासा की क्यूबसैट लॉन्च इनिशिएटिव (सीएलआई) के तहत इसकी लॉन्च व्यवस्था की गई थी।

कैनवास एक 4यू क्यूबसैट है, जिसे कोलोराडो यूनिवर्सिटी, बोल्डर ने विकसित किया है। इसका मुख्य काम पृथ्वी की निचली कक्षा से बहुत कम आवृत्ति वाली (वीएलएफ) रेडियो तरंगों को मापना है। ये तरंगें बिजली गिरने और जमीन पर स्थित ट्रांसमीटर्स से उत्पन्न होती हैं। यह मापता है कि ये तरंगें पृथ्वी के आयनमंडल (वायुमंडल का ऊपरी विद्युत आवेशित हिस्सा) से गुजरकर मैग्नेटोस्फीयर तक कितनी मात्रा में पहुंचती हैं। वीएलएफ तरंगें अंतरिक्ष में फंसे हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते को थोड़ा बदल सकती हैं। इससे कभी-कभी ये इलेक्ट्रॉन विकिरण पट्टियों से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। कैनवास इन तरंगों के प्रभाव को समझकर स्पेस वेदर के मॉडलों को मजबूत बनाएगा। इससे स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स और पृथ्वी पर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में सुधार होगा। मिशन के दौरान कैनवास दो मुख्य उपकरणों का उपयोग करेगा एक त्रि-अक्षीय सर्च कॉइल मैग्नेटोमीटर और एक द्वि-अक्षीय एसी विद्युत क्षेत्र सेंसर। इनकी मदद से यह वीएलएफ तरंगों की शक्ति और दिशा का पता लगाएगा। बिजली गिरने की घटनाओं की तुलना विश्वव्यापी बिजली नेटवर्क के डेटा से करके यह जलवायु संबंधी अध्ययन करेगा कि ये तरंगें आयनमंडल से कैसे गुजरती हैं।

बता दें, नासा ने साल 2021 में सीएलआई के तहत कैनवास को चुना था। यह कम लागत वाला मिशन छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतरिक्ष हार्डवेयर डिजाइन करने, विकसित करने और बनाने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। नासा का लॉन्च सर्विसेज प्रोग्राम इस पहल को संचालित करने में अहम योगदान दे रहा है। कैनवास ईलाना 55 लॉन्च ग्रुपिंग का भी हिस्सा है। अगले एक वर्ष तक कैनवास निरंतर डाटा एकत्र करेगा। यह डाटा पृथ्वी से अंतरिक्ष में ऊर्जा के प्रवाह को समझने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

फ्लाई 91 में 4 घंटे की भयावह उड़ान, रोते-बिलखते भगवान से प्रार्थना करते रहे यात्री

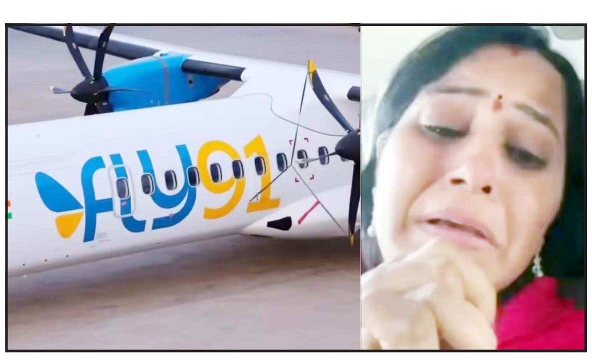

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के हैदराबाद से कर्नाटक के हुबली जा रही फ्लाई 91 की उड़ान ने एक बार फिर यात्रियों के उड़ान अनुभव को डरावना बना दिया है। अपनी डेढ़ घंटे की नियमित उड़ान के दौरान विमान अचानक तकनीकी समस्या की चपेट में आ गया, जिसके बाद विमान 7 घंटे बाद जमीन पर उतरा। इस बीच, करीब 4 घंटे तक विमान आसमान में मंडराता रहा, जिससे विमान में बैठे यात्री रोने-बिलखने लगे और भगवान को याद करने लगे।

घटना के एक दिन बाद हैदराबाद-हुबली की फ्लाई91 विमान में सवार यात्रियों का वीडियो सामने आया है, जिसमें विमान के अंदर की गतिविधि दिख रही है। यात्री चिल्लाते और रोते सुनाई पड़ रहे हैं, जबकि एक महिला रोते हुए और प्रार्थना करते दिख रही हैं। अरे यार... वो ऐसा क्यों कर रहा है, एक आदमी को चिल्लाते हुए सुना जा सकता था। रो मत, रो मत, कुछ नहीं होता, रुको। वीडियो में एक और आवाज सुनाई देती है।

घटना के बाद एयरलाइंस ने कहा, जैसा कि मीडिया के कुछ हिस्सों में बताया जा रहा है, हैदराबाद-हुबली उड़ान आईसी-3401 में कोई तकनीकी खराबी नहीं आई। उड़ान हैदराबाद से दोपहर 3 बजे रवाना हुई। हुबली पहुंचने पर खराब मौसम के कारण उड़ान को मानक प्रोटोकॉल के अनुसार बेंगलुरु की ओर मोड़ दिया गया। सुरक्षा से जरा भी समझौता नहीं किया गया। विमान को बेंगलुरु की ओर मोड़ना मानक संचालन प्रक्रिया का हिस्सा था। यह सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक है।

फ्लाई 91 एयरलाइंस की उड़ान आईसी-3401 (एटीआर टर्बोप्रॉप एटी7) दोपहर लगभग 3 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई थी। उसे शाम 4:30 बजे हुबली उतरना था। जैसे ही विमान हुबली के पास पहुंचा, उसमें तकनीकी खराबी की जानकारी मिली और पायलट ने लैंडिंग रद्द कर दी। इस दौरान विमान करीब 4 घंटे तक मुंडगोड, दावणगेरे और शिवमोग्गा सहित कई क्षेत्रों के ऊपर ही मंडराता रहा और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के प्रयास करता रहा।

भारत-दक्षिण कोरिया चिप से लेकर जहाज बनाने तक में सहयोगी, अब एक दूसरे देश में कर सकेंगे क्यूआर कोड से भुगतान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और दक्षिण कोरिया अब चिप से लेकर जहाज बनाने तक में सहयोगी बनेंगे। पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद यह सहमति बनाई गई। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच बड़ा इलेक्ट्रानिक पेमेंट समझौता हुआ है। इसके तहत अब एक दूसरे देशों के नागरिक भारत और दक्षिण कोरिया में आने-जाने के दौरान क्यूआर कोड के जरिये आसानी से भुगतान कर सकेंगे।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने कहा, भारत और दक्षिण कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को जोड़ने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिक जब एक-दूसरे के देश जाएंगे तो वहां स्थानीय क्यूआर कोड सिस्टम का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे। यह कदम आपसी यात्राओं को और भी सुविधाजनक बनाएगा। हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक के दौरान ली जे-म्युंग ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान उन्होंने पौधरोपण भी किया। भारत-दक्षिण कोरिया के द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर फोकस किया गया। भारत और दक्षिण कोरिया ने सहमति जताई कि वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल और बढ़ते व्यापारिक व्यवधानों के बीच अपने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को और मजबूत बनाने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर शांति एवं स्थिरता का सशक्त संदेश दे रहे हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में धाकड़ खिलाड़ी की एंट्री, एमआई में भी लौटा खतरनाक ऑलराउंडर

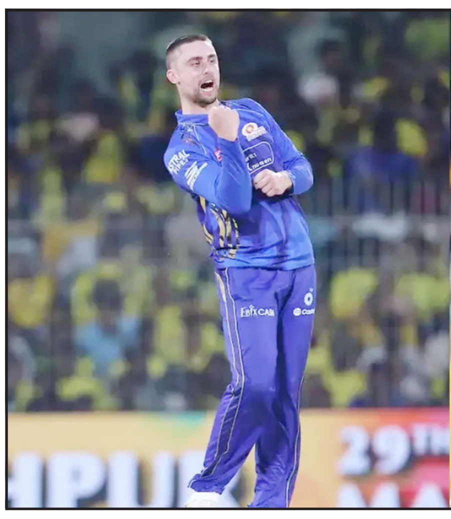
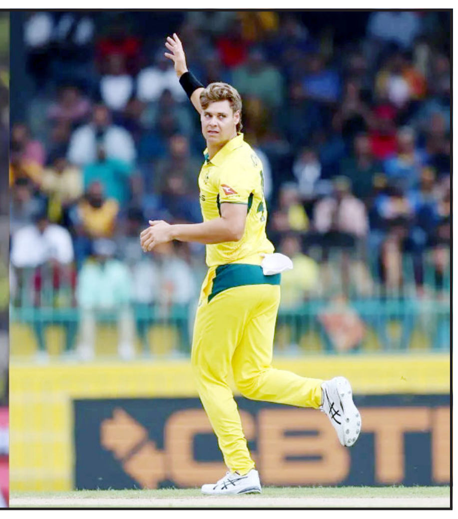

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2026 में पांच-पांच बार की चैंपियन दो धाकड़ टीमों के लिए सबकुछ खास नहीं चल रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो टीम इंजरी की वजह से परेशान है। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम आखिरकार लगातार चार हार के बाद जीत की पटरी पर लौटी है। अब इन दोनों बड़ी टीमों के लिए मंगलवार (21 अप्रैल 2026) की शाम दो अच्छी खबरें आई हैं। खास बात यह है कि गुरुवार को चेन्नई और मुंबई का सामना होना है, उससे पहले दोनों टीमों में दो धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी हो गई है।

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जहां पहले नाथन एलिस और फिर खलील अहमद के बाहर होने से परेशान थी। अब स्पेन्सर जॉनसन की टीम में वापसी हो गई है। फ्रेंचाइजी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है कि जॉनसन अब टीम के साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि स्पेन्सर जॉनसन को नाथन एलिस के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया था, लेकिन वह इंजरी से रिकवर कर रहे थे। अब जॉनसन के आने से कुछ हद तक टीम की गेंदबाजी की समस्या हल हो सकती है। क्रिकबज की जानकारी के मुताबिक मुंबई इंडियंस के कैंप में इंग्लैंड के खतरनाक ऑलराउंडर विल जैक्स की एंट्री हो चुकी है। जैक्स चोटिल थे और अब वह रिकवरी के बाद टीम के साथ जुड़ चुके हैं। जैक्स भारत लौटे हैं और अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग करते नजर आए। मुंबई ने गुजरात के खिलाफ 99 रन से शानदार जीत दर्ज करते हुए जीत की पटरी पर वापसी की थी। अब विल जैक्स के आने से टीम के पास एक अच्छे लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाजी का विकल्प बढ़ गया है।

मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 का स्क्वाड: क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, कॉर्बिन बॉश, मिचेल सैंटनर, अश्विनी कुमार, विल जैक्स, मयंक मारकंडे, रघु शर्मा, राज बावा, रॉबिन मिंज, अल्लाह गजनफर, दानिश मालेवार, कृष भगत, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार।

चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 का स्क्वाड: महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवर्टन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्क्स, खलील अहमद (पूरे सीजन से बाहर), आयुष म्हात्रे (पूरे सीजन से बाहर)।

आईपीएल 2026 में सीएसके लगातार इंजरी से परेशान है। अब आयुष म्हात्रे भी पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। ऐसे में अश्विन की तरफ से इंजरी से जूझ रही टीमों को खास सलाह दी गई है कि वह बीच सीजन स्थ्डुट्ठ क्क्ष्यडु4द्गह्ल नियम का इस्तेमाल कर सकती हैं।

वैभव सूर्यवंशी नंबर 1, प्रियांश-अभिषेक भी टॉप 5 में, तिलक ने की इशान की बराबरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2026 में संजू सैमसन के बाद तिलक वर्मा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। उन्होंने (20 अप्रैल 2026) को गुजरात टाइटंस के खिलाफ 45 गेंद पर 101 रन की नाबाद पारी खेली। यह तिलक का आईपीएल में पहला शतक है। उनके लिए यह सीजन अभी तक फ्लाप साबित हो रहा था और मुंबई भी हार रही थी। जैसे ही तिलक का बल्ला चला तो मुंबई ने भी 99 रन से गुजरात को मात दी।

इस शतक के साथ सबसे तेज शतक लगाने के मामले में तिलक वर्मा अब इशान किशन और मयंक अग्रवाल की बराबरी करते हुए, संयुक्त रूप से पांचवें सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने। अगर भारत के लिए आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की बात करें तो 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं वहीं अभिषेक शर्मा और प्रियांश आर्या भी लिस्ट में टॉप 5 का हिस्सा हैं। इसके अलावा विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाजों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जबकि ओवरऑल पूरी दुनियाभर के हिसाब से तिलक का यह शतक संयुक्त रूप से 10वां सबसे तेज आईपीएल शतक था। टॉप 10 भारतीयों के अलावा पांच ऐसे भारतीय बल्लेबाज भी हैं जिन्होंने 49 गेंद पर आईपीएल में शतक जड़ा है। रिद्दिमान साहा, रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल ने 49-49 गेंदों पर आईपीएल में शतक लगाया है। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। टीम के इन फॉर्म बल्लेबाज आयुष म्हात्रे अब पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में आयुष चोटिल हुए थे, अब उन्हें रिकवरी में 6 से 12 हफ्ते लगेंगे।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे की स्क्रैप से कमाई 6,800 करोड़ रुपए के पार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में कबाड़ (स्क्रैप) बेचकर 6,813.86 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो 6,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से अधिक है। इस उपलब्धि की खास बात यह है कि स्क्रैप बेचकर कमाई (मॉनिटाइजेशन) में रेलवे ने अपने लक्ष्य को काफी हद तक पार कर लिया है। इससे पहले 2024-25 में भी रेलवे ने 5,400 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 6,641.78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। लगातार मिल रही यह सफलता दिखाती है कि रेलवे अपने डिपो, यार्ड और वर्कशॉप में पड़े पुराने और बेकार सामान से सही कमाई कर रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से न सिर्फ रेलवे की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि इससे जगह भी खाली हो रही है और रीसाइक्लिंग के जरिए पर्यावरण को भी फायदा मिल रहा है। साथ ही, पुराने सामान के निपटान की पारदर्शी व्यवस्था से कामकाज और बेहतर हुआ है।स्क्रैप से कमाई के साथ-साथ टिकट के अलावा होने वाली आय (नॉन-फेयर रेवेन्यू - एनएफआर) भी रेलवे की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। स्टेशन विकास, विज्ञापन और रेलवे की संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग से होने वाली यह कमाई पिछले पांच साल में लगातार बढ़ी है।2021-22 में यह आय करीब 290 करोड़ रुपए थी, जो 2025-26 में बढ़कर 777.76 करोड़ रुपए हो गई, यानी करीब 168 प्रतिशत की बढ़त हुई।सरकार ने कहा कि इस अतिरिक्त आय से रेलवे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्रियों की सुविधाओं में निवेश कर रहा है। इनमें बेहतर स्टेशन सुविधाएं, साफ-सफाई, डिजिटल सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है और यह सब बिना किराया बढ़ाए किया जा रहा है। नॉन-फेयर कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांडेड दुकानों की शुरुआत भी की है। इसके तहत कंपनी के स्वामित्व वाली सिंगल-ब्रांड आउटलेट्स खोलने के लिए ठेके दिए गए हैं और अब तक 22 प्रीमियम ब्रांड्स को जगह दी जा चुकी है। इन दुकानों से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रेलवे की आय भी बढ़ेगी।

आईपीएल में खिलाड़ी को लोन पर लेने का क्या है नियम?

अश्विन ने CSK को दी RCB के प्लेयर को 'उधार' लेने की सलाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2026 में कई फ्रेंचाइजी बीच सीजन और सीजन के पहले से ही चोट की समस्याओं से जूझ रही हैं। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स इससे ज्यादा ही पीड़ित है। टीम ने अभी तक इस सीजन से तीन बड़े खिलाड़ी गंवा दिए हैं। आयुष म्हात्रे बेहतरीन फॉर्म में थे लेकिन अंडर 19 विश्व विजेता भारतीय टीम के कप्तान को भी पूरे सीजन से बाहर होना पड़ा है। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने सीएसके को खास सलाह दी है। इस सलाह में दिग्गज स्पिनर ने एक ऐसे नियम का जिक्र किया है जो शायद ही कुछ लोग जानते होंगे।

जी, हां यह नियम बीच सीजन आईपीएल में किसी टीम को अन्य टीम से खिलाड़ी उधार लेने की इजाजत देता है, लेकिन इसमें एक खास बात भी है। यह नियम सिर्फ तब तक ही लागू है जब तक फ्रेंचाइजीज ने सीजन के 7-7 मैच (यानी ग्रुप स्टेज के आधे मैच) नहीं खेल हैं। इस लिहाज से सीएसके ने अभी 6 मैच खेले हैं और 7वें मैच से पहले अश्विन की सलाह के मुताबिक वह लोन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

रविचंद्रन अश्विन ने मंगलवार (21 अप्रैल 2026) को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'कई चोट की समस्याओं के देखते हुए, लोन विंडो बंद होने से पहले (7 मैचों के मार्क पर पहुंचने से पहले) यह एक अच्छा आइडिया होगा कि आरसीबी से इस (विहान मल्होत्रा की तस्वीर के साथ शेयर) प्रतिभाशाली खिलाड़ी को लोन पर लिया जाएगा। उन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है और वह लोन पर लिए जा सकते हैं। अगर विहान नहीं तो अभिज्ञान कुंडू एक अच्छा बाएं हाथ का ऑप्शन हो सकते हैं भविष्य के मद्देनजर।'

अश्विन ने अपने पोस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स का नाम नहीं लिखा। मगर आयुष म्हात्रे चोटिल होकर सीजन से बाहर हैं और सबसे ज्यादा सीएसके ही बल्लेबाजों को लेकर परेशान है। उनका इशारा साफ है कि सीएसके अगर चाहे तो आरसीबी से विहान मल्होत्रा को लोन पर ले सकती है। या फिर अभिज्ञान कुंडू जो आईपीएल ऑक्शन का हिस्सा नहीं थे, उनके नाम पर भी टीम एक ठोस भविष्य के लिहाज से सोच सकती है। अब ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर यह लोन नियम है क्या? मैचों की संख्या के साथ-साथ इस नियम की कई अन्य शर्तें भी हैं। आइए इस नियम को जानते हैं विस्तार से:- आईपीएल 2026 में लगातार सीएसके की टीम इंजरी से परेशान है। ऐसे में अब टीम के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है Loan Player नियम। जैसा कि हमने बताया कि यह नियम तब तक ही इस्तेमाल हो सकता है जब तक टीमों ने 7-7 मैच नहीं खेले हैं। एक बार 7-7 मैच पूरे होने के बाद यह नियम नहीं यूज किया जा सकता है। यानी अभी सीएसके के पास मौका है कि वह प्लेयर उधार ले सकते हैं। अब एक-एक करके जानते हैं इस नियम की सभी शर्तें क्या हैं? नहीं, सिर्फ अधिकतम 2 मैच खेलने वाले (प्लेइंग 11 में होने या बतौर कनकशन शामिल होने) खिलाड़ी इस नियम के तहत उधार लिए जा सकते हैं। यानी ऐसे खिलाड़ी भी हो सकते हैं जिन्होंने आईपीएल डेब्यू नहीं किया है और किसी अन्य फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। मगर इसकी कंडीशन एक यह भी है कि जैसे सीएसके किसी एक खिलाड़ी को आरसीबी से लोन पर लेती है, तो वह खिलाड़ी आरसीबी के खिलाफ मैच में नहीं उतर सकता है। साथ ही इस नियम के तहत लोन पर ट्रेड किए जाने वाले प्लेयर की सहमति भी जरूरी होती है।

लोन पर लिए गए खिलाड़ी को कौन सी टीम पैसा देती है: जिस फ्रेंचाइजी ने आईपीएल ऑक्शन के समय लोन पर ट्रेड होने वाले खिलाड़ी को खरीदा था, वही फ्रेंचाइजी तय कॉन्ट्रैक्ट या बोली के मुताबिक पैसा उस खिलाड़ी को देती है। वहीं लोन के बाद जिस फ्रेंचाइजी ने उसे खरीदा होता है वही टीम प्रति मैच फीस के हिसाब से उस खिलाड़ी का भुगतान करती है। साथ ही जो टीम लोन पर खिलाड़ी को लेती है उसे दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ लोन की फीस पर सहमति बनानी होती है। इसका आईपीएल के सैलरी कैप से कोई मतलब नहीं होता है।

कितने खिलाड़ी लोन पर लिए जा सकते हैं : आईपीएल के नियम के मुताबिक एक फ्रेंचाइजी एक सीजन के लिए सिर्फ अधिकतम दो खिलाड़ियों को ही किसी एक टीम से लोन पर ले सकती है। इस लोन ट्रेड की अवधि सिर्फ उस सीजन के अंत तक ही मान्य होती है। जैसे आईपीएल 2026 में कोई खिलाड़ी लोन पर लिया गया तो सीजन खत्म होने के बाद उसे वापस अपनी मूल टीम के स्क्वाड का ही हिस्सा माना जाएगा। आईपीएल में तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 19वें सीजन के 30वें मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 45 गेंद पर बेहतरीन शतक जड़ा। इसी के साथ वह संयुक्त रूप से 45 गेंद पर पांचवां सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने।

सोना-चांदी खरीदने वालों की लगी लॉटरी, एक झटके में औंधे मुंह गिरे दाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी खरीदने का मन बना रहे ग्राहकों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बीते सप्ताह दोनों कीमती धातुओं के दाम में जो जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी, उस पर हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन अचानक ब्रेक लग गया है। सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (पर वायदा कारोबार शुरू होते ही सोना और चांदी धड़ाम से नीचे आ गिरे। एक ही झटके में चांदी की कीमतों में 5000 रुपये से ज्यादा की भारी गिरावट दर्ज की गई। इस ताजा गिरावट के बाद अब चांदी अपने उच्चतम स्तर (लाइफ टाइम हाई) से 1.87 लाख रुपये से ज्यादा सस्ती हो चुकी है, जबकि सोने के भाव में भी तगड़ी कमी आई है।

एमसीएक्स पर कारोबार की शुरुआत होते ही बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। 5 मई की एक्सपायरी वाली चांदी का भाव बीते दिनों 2,57,142 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन सुबह खुलते ही यह धड़ाम होकर 2,51,785 रुपये पर आ गया। इस हिसाब से बाजार खुलते ही चांदी सीधे 5,357 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई। अगर चांदी के सर्वकालिक उच्च स्तर से इस गिरावट की तुलना करें, तो यह अब 1,87,552 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती मिल रही है। गौरतलब है कि इसी साल जनवरी महीने में चांदी का वायदा भाव पहली बार 4 लाख रुपये के पार निकला था और 4,39,337 रुपये प्रति किलो का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था।

सोने की चमक भी पड़ी फीकी, 50 हजार रुपये से ज्यादा सस्ता हुआ गोल्डचांदी की ही तर्ज पर एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में भी बड़ी गिरावट हावी रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट अपने पिछले कारोबारी बंद के मुकाबले ओपनिंग के साथ ही 1780 रुपये कम हो गया। पिछले शुक्रवार को 5 जून की एक्सपायरी वाले वायदा सोने का भाव 1,54,609 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जो औंधे मुंह गिरकर 1,52,829 रुपये पर आ गया। इस बड़ी गिरावट के साथ अब सोना अपने लाइफ टाइम हाई लेवल 2,02,984 रुपये से सीधे 50,155 रुपये सस्ता मिल रहा है। शादी-ब्याह के सीजन में ग्राहकों के लिए यह किसी बड़े सुनहरे मौके से कम नहीं है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति के बाद से अब तक दोनों कीमती धातुओं के भाव में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमलों की शुरुआत की थी, उससे ठीक एक दिन पहले यानी 27 फरवरी को एमसीएक्स पर चांदी 2,82,644 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। ताजा कीमतों से तुलना करें तो इस दौरान चांदी 30,859 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है। इसी तरह 27 फरवरी को सोना 1,65,659 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और तब से अब तक सोने के रेट में भी 12,830 रुपये की कमी आ चुकी है। हालांकि, बीते हफ्ते सिर्फ चार कारोबारी दिनों में चांदी 14 हजार और सोना करीब 2 हजार रुपये महंगा हुआ था, लेकिन सोमवार की इस ताजा गिरावट ने बाजार का सारा गणित पलट कर रख दिया है।अगर चांदी के सर्वकालिक उच्च स्तर से इस गिरावट की तुलना करें, तो यह अब 1,87,552 रुपये प्रति तक सस्ती मिल रही है।

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह अवमानना के दोषी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि भोला नाथ सिंह ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में सजा को लेकर अगले महीने चार मई को सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भोलानाथ सिंह को इस बीच कोई सुधारात्मक कदम उठाकर अपनी गलती सुधारने का अवसर भी दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने 20 अप्रैल को हॉकी इंडिया की चुनी हुई उपायक्ष सईदा आसिमा अली की याचिका पर यह फैसला सुनाया। आसिमा अली ने आरोप लगाया था कि खेल संस्था के पदाधिकारियों ने 17 जनवरी 2025 को दिए गए एक आदेश का पालन नहीं किया। अदालत ने कहा कि उसके निर्देशानुसार हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों को जरूरी लिंक देने थे, ताकि वह कार्यकारी बोर्ड की सभी बैठकों में हिस्सा ले पाएं, लेकिन चार जुलाई 2025 और 27 जुलाई 2025 को हुई बैठकों के लिए वे ऐसा करने में नाकाम रहे।

सरकार ने एक दिन में डिलीवर किए 53.5 लाख एलपीजी सिलेंडर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भले ही पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बिना किसी रुकावट के जारी है। एक ही दिन में 53.5 लाख से ज्यादा सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, जिससे नागरिकों को ईंधन की निर्बाध उपलब्धता का भरोसा दिलाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, बुकिंग के मुकाबले घरेलू एलपीजी की डिलीवरी सामान्य बनी हुई है।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 18 अप्रैल, 2026 को 53.5 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर सिलेंडरों की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

सरकार ने घरों तक सप्लाई को प्राथमिकता दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा संकट के दौरान खाना पकाने का जरूरी ईंधन उपलब्ध रहे। डिजिटल माध्यमों को अपनाने में भी काफी बढ़ोतरी हुई है; लगभग 98 प्रतिशत एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन की जा रही हैं, जबकि 93 प्रतिशत से अधिक डिलीवरी अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) के जरिए प्रमाणित की जा रही हैं ताकि सिलेंडरों का गलत इस्तेमाल या हेरफेर रोका जा सके।सप्लाई के मोर्चे पर, सरकार ने घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी सेगमेंट के लिए 100 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की है। कमर्शियल एलपीजी के लिए, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, दवा कंपनियों, स्टील, ऑटोमोबाइल और कृषि जैसे जरूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन दिया गया है।इसके अलावा, प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई दोगुनी कर दी गई है; यह फैसला मार्च महीने में खपत के पिछले पैटर्न के आधार पर लिया गया है।एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए, केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन भी उपलब्ध कराए गए हैं।

कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज जैसी प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे राज्यों को दिए जाने वाले कोयले के आवंटन में बढ़ोतरी करें, ताकि छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं तक इसकी सप्लाई सुनिश्चित हो सके।राज्यों को यह सलाह भी दी गई है कि वे घरेलू और कमर्शियल, दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करें। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाकर संकट से पहले के स्तर का लगभग 70 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसमें सुधारों से जुड़े आवंटन भी शामिल हैं।

संपादकीय

पहल के पीछे के इरादे पर शक

विदेशी चंदे की भारत में क्या भूमिका रही है और इसका किस हद तक अवांछित उद्देश्यों के लिए उपयोग हुआ है, इस बारे में स्पष्टता बनाने की जरूरत है। बेहतर होगा कि केंद्र इस बारे में श्वेत पत्र जारी करे।

संसद के चालू सत्र में विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक ना पारित कराने के केंद्र के एलान से इस बारे में टकराव फिलहाल टल गया है। केंद्र ने कहा कि केरल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा किया। वैसे, कहा यह भी जा सकता है कि इसी चुनाव के कारण विधेयक को फिलहाल टालने पर केंद्र इतनी आसानी से राजी हो गया। वरना, विवादित विधेयकों को बहुमत के जोर से पारित कराने का उसका रिकॉर्ड जग-जाहिर है। केरल में भाजपा की नजर भी ईसाई मतदाताओं पर है; इसके बावजूद कि भाजपा और उसके सहमना संगठनों का लंबे समय से इल्जाम है कि ईसाई संस्थाएं विदेशी धन का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करती हैं।

और संभवत: इसीलिए एफसीआरए के नियमों में बदलाव को ईसाइयों ने अपने खिलाफ माना है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इसे खतरनाक और चिंताजनक बताया है, जबकि केरल और अन्य राज्यों में चर्च समूहों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। बहरहाल, विदेशी चंदे को सिर्फ सांप्रदायिक संदर्भ में देखना सही नजरिया नहीं है। बेहतर होगा कि ऐसे चंदे की व्यापक भूमिका पर विचार- विमर्श किया जाए। विदेशी चंदे की भारत में क्या भूमिका रही है और इसका किस हद तक अवांछित उद्देश्यों के लिए उपयोग हुआ है, इस बारे में स्पष्टता बनाने की जरूरत है। बेहतर होता कि केंद्र इस बारे में श्वेत पत्र जारी करता। उससे इस बारे में ठोस समझ बनाने में मदद मिलती। ले

किन वर्तमान सत्ताधारी पार्टी पर आरोप है कि वह महज कुछ हलकों के लिए चंदे के स्त्रोत रोकना चाहती है, जबकि अपने सहमना संगठनों के लिए वह इसका रास्ता खुला रखना चाहती है। इसलिए उसकी ये पहल विवादास्पद हो गई है। वरना, हर देश का यह संप्रभु अधिकार है कि वह अपने यहां धन या अन्य माध्यमों से विदेशी हस्तक्षेप को नियंत्रित और विनियमित करे। ऐसा निष्पक्ष रुख एवं अधिकतम सहमति के साथ किया जाए, तो विवाद की संभावना न्यूनतम रहेगी। जबकि पहल के पीछे के इरादे पर शक हो, तो बात बिगड़ जाती है। ऐसा ही इस मामले में हुआ है।

भारत व दक्षिण कोरिया के बीच हुई नई डील के सियासी निहितार्थ

दुनियाभर में भारत की कूटनीति अपने अनोखे अंदाज के लिए चर्चित रहती आई है, क्योंकि हम तमाम हानि-लाभ की परवाह किए बगैर वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवंतु सुखिन: के सभ्यता-संस्कृतिगत सिद्धांतों को अमलीजामा पहनाते आए हैं। हालांकि कोई इसे गुटनिरपेक्षता समझता है तो कोई निज स्वार्थपरकता, जो गलत भी नहीं है। आखिर बिना स्वार्थ साधे परमार्थ भी किया जाए तो कैसे? इसलिए व्यवहारम फलदायकम हमारा मूलमंत्र है। भारत और दसक्षिण कोरिया के बीच हुई नई डील (व्यापार, तकनीक, रक्षा और ऊर्जा सहयोग) को इसी नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि इससे ही द्विपक्षीय रिश्तों के साथ साथ हिंद प्रशांत के रणनीतिक संतुलन में भी गहरे सियासी निहितार्थ निकलते हैं। आइए क्रमबद्ध तरीके से इसे समझते हैं-

पहला, भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति मजबूत होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। जहां भारत दक्षिण कोरिया की 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' को आगे बढ़ाने के घोषणाओं से भारत को उत्तर पूर्व एशिया और इंडो पैसिफिक में एक अलग मध्य शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद मिलती है। वहीं, दक्षिण कोरिया का भारत नेतृत्व वाली पहलों जैसे इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और सोलर एलायंस में शामिल होना भारत की 'मल्टी एलायंस' रणनीति को वैधता देता है।

दूसरा, अमेरिकी चीन टकराव में एक मजबूत तीसरा धुरा, जो संतुलन कारी साबित हो सकता है। दक्षिण कोरिया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अमेरिका का मजबूत सहयोगी है, अब भारत के साथ चिप, एआई, ऊर्जा और जल मार्ग जैसे क्षेत्रों में गहरा तकनीकी आर्थिक सहयोग बना रहा है; यह चीन केंद्रित आपूर्ति श्रृंखला से बचने के लिए 'डी-रिस्किंग' रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इससे भारत, अमेरिका जैसे देशों के लिए चीन के बिना एक वैकल्पिक टेक और विनिर्माण हब बनने की दिशा में आगे बढ़ता है, जिससे हिंद प्रशांत में चीन विरोधी छोटे गुटों के लिए भारत का भू रणनीतिक मूल्य बढ़ता है। भारत इसे भुनाने में भी पीछे नहीं रहता, ताकि भारत के पड़ोसियों से चीन के बेहतर होते सम्बन्धों को उसके पड़ोस से साधकर अपना हित वर्द्धन किया जा सके।

तीसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर इसलिए कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने के साथ ही चिप से शिप जैसी डील्स को रफ्तार देने से दोनों देश आपूर्ति श्रृंखलाओं में आपसी निर्भरता बढ़ा रहे हैं। इससे किसी भी एक बड़े खिलाड़ी (जैसे चीन या अमेरिका) के दबाव से निकलने की लचीलापन बढ़ता है। इसके अलावा, दोनों देशों ने ऊर्जा आपूर्ति, आर्थिक सुरक्षा वार्ता और नौसैनिक लॉजिस्टिक सहयोग पर भी जोर दिया है, जिससे दक्षिण कोरिया को भी भारत के माध्यम से ईरान और मध्य पूर्व से ऊर्जा तक पहुंच के विकल्प मिलते हैं। इससे भारत को विभिन्न तरह की मजबूती मिलती है। चौथा, चीन और उत्तर कोरिया पर निर्देशित संदेश का रणनीतिक फायदा मिलता है।

भारत दक्षिण कोरिया की बढ़ती रक्षा और तकनीकी साझेदारी, खासकर चिप, एआई, डिफेंस इंडस्ट्री और नौसैनिक लॉजिस्टिक पर काम, क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर चीन की समुद्री दबाव रणनीति के खिलाफ एक छोटा बफर बनाती है। यह उत्तर कोरिया के लिए भी यह ज्यादा टेंशन वाला है, क्योंकि दक्षिण कोरिया भारत सहयोग से उसके अपने देश के खिलाफ एक और बाहरी 'प्रतिनिधित्व' बनता है, जो चीन रूस के साथ उसके एकमात्र बड़े सहयोग पर भी राजनीतिक दबाव डाल सकता है।

पांचवां, भारत के भीतरी राजनीतिक लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के लिए यह डील एक ऐसा नारा बनती है जिससे सत्ताधारी गठबंधन यह दिखाने की कोशिश कर सकता है कि 'मल्टी एलायंस विदेश नीति' और तकनीक आधारित 'वैश्विक फैक्टरी' की तस्वीर धीरे धीरे असली हो रही है। इससे चुनावी राजनीति में 'मजबूत वैश्विक भागीदार' बनने की चित्रण रणनीति मजबूत होती है, खासकर जब भारत अमेरिका, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग अलग गैर आधिकारिक गुटों में एक बड़ा खिलाड़ी बन रहा है। चूंकि इससे भारतीय प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, इसलिए सराहनीय पहल है।राजनीति

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुए 15 समझौतों में सीधे तौर पर 'चिप' (सेमीकंडक्टर/एआई टेक) और 'शिप/पोत' (जहाज निर्माण, नौवहन, स्टील, बंदरगाह) से जुड़े कुछ मुख्य सहमति पत्रक इस प्रकार हैं:- पहला, चिप (सेमीकंडक्टर/एआई/टेक) से जुड़े समझौते- एआइ, सेमीकंडक्टर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में समझौते: भारत दक्षिण कोरिया के बीच एआइ, सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कई सहमति पत्रक (रूश्ह्य) पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें साझा शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्टार्टअप/कंपनी स्तरीय सहयोग जैसे बिंदु शामिल हैं।

क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और आपूर्ति शृंखला सहयोग (आर्थिक सुरक्षा वार्ता): भारत कोरिया 'आर्थिक सुरक्षा वार्ता' थीम के तहत चिप आधारित क्रिटिकल टेक (सेमीकंडक्टर, एक्ज़ीक्यूटिव ग्रेड टेक) की आपूर्ति शृंखला में सहयोग बढ़ाने के रूश भी शामिल हैं। दूसरा, शिप/जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र से जुड़े समझौते- समाचारों में '15 समझौतों' की लिस्ट के तौर पर निम्न बिंदु विशेष रूप से पोत निर्माण और समुद्री विकास सहयोग से सीधे जुड़े हैं:

पोत निर्माण: भारत दक्षिण कोरिया के बीच जहाज निर्माण और जहाज हार्डवेयर डिज़ाइन/टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर एक या अधिक सहमति पत्रक (रूश्ह्य) हुए, जिनका उद्देश्य भारत के डॉकयार्ड्स और प्राइवेट शिपबिल्डर्स को कोरिया की उन्नत जहाज निर्माण तकनीक से जोड़ना है।

स्टील/इस्पात आपूर्ति श्रंखला के लिए तकनीक और व्यापार: इस्पात उत्पादन और आपूर्ति श्रंखला (जो शिपबिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण है) पर तकनीक आधारित सहमति पत्रक (रूश) शामिल, जिससे भारतीय स्टील मिलों और कोरियाई शिपबिल्डर्स के बीच सीधा बंधन बढ़ेगा।

समुद्री विरासत समझौता : भारत कोरिया के बीच समुद्री इतिहास और संस्कृति संरक्षण, म्यूजियम सहयोग और अंडरवाटर आर्कियोलॉजी जैसे प्रोजेक्टों पर सहमति पत्रक (Mo) हुआ, जो राजनीतिक सांस्कृतिक स्तर पर समुद्र केंद्रित विज़न को बढ़ावा देता है।

पोर्ट्स क्षेत्र में सहयोग: भारत और दक्षिण कोरिया ने पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण और पोर्ट बेस्ड लॉजिस्टिक्स पर अलग सहमति पत्रक शामिल किया है, जो 'चिप से शिप' नारे के तहत लॉजिस्टिक्स डिजिटल हार्डवेयर चेन को जोड़ता है।

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुए 15 समझौतों में 'चिप' और 'शिप' के अलावा कई अन्य प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:- पहला, ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक सुरक्षा वार्ता पर एक सहमति पत्रक: दोनों देश लिक्विड नेचुरल गैस, रिन्यूएबल एनर्जी और 'क्रिटिकल टेक' आपूर्ति शृंखला के संदर्भ में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत कोरिया 'ऊर्जा आपूर्ति' सहमति पत्रक ने ऊर्जा आपूर्ति विविधता और आर्थिक राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। दूसरा, विज्ञान, अनुसंधान और इनोवेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान : भारत की राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एजेंसियों और दक्षिण कोरिया के विज्ञान तकनीकी संस्थानों के बीच शोध और इनोवेशन आधारित सहमति पत्रक (रूश) शामिल हैं।

वहीं, नवीनतम तकनीकों का आदान प्रदान (लेज़र, फोटोनिक्स जैसे क्षेत्रों में): इस तरह के समझौते भारत को दक्षिण कोरिया की उन्नत रिसर्च क्षमताओं से जोड़ते हैं।

तीसरा, व्यापार, विकास और निवेश, व्यापार और विकास बैंक सहमति पत्रक: भारत के विकास बैंक (जैसे EXIM या DFDC जैसी संस्थाएँ) और दक्षिण कोरिया आधिकृत विकास वित्त संस्थानों के बीच सहयोग रूश शामिल, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तपोषण संरचना को सुगम बनाएगा। व्यापार लक्ष्य (2030 तक 50 अरब डॉलर) को मजबूत करने के लिए व्यापार नीति, निवेश और मानक समन्वय पर कई विशेष सहमति पत्रक शामिल है। चतुर्थ, स्वास्थ्य, फार्मा और जीव विज्ञान, स्वास्थ्य और जीव विज्ञान शोध: भारत के जैव वैज्ञानिक शोध संस्थानों और दक्षिण कोरिया के फार्मा/बायोटेक संस्थानों के बीच शोध सहयोग सहमति पत्रक है, जिसमें दवाओं, वैक्सीन और जैव तकनीकों के साझा अध्ययन शामिल हैं। इससे भारतीय फार्मा और जैव उद्योग को उन्नत टेक्नोलॉजी और वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने में मदद मिलेगी।

आखिर पारित क्यों नहीं हो पाया महिला आरक्षण, परिसीमन संविधान संशोधन बिल?

लोकसभा सरकार द्वारा पेश महिला आरक्षण, परिसीमन संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो सका है क्योंकि सरकार दो तिहाई समर्थन नहीं जुटा सकी इसलिए 298 मत लाकर गिर गया। विपक्ष ने कोई सहयोग नहीं किया कांग्रेस,सपा, डीएमके, तुड़मूल कांग्रेस, बीजेडी, सीपीएम, सीपीई, RSP, सहित डालो विरोध में 230 का अकड़ा जूता लिया जबकि सरकार को 336 मतों की आवश्यकता थी।

इससे पहले लोकसभा में जमकर बहस हुई।बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, निशिकांत दुबे, के सी वेणुगोपाल आदि नेताओं ने भाग लिया। इस बिल के गिरने से सरकार अचरज में नहीं है उसे पहले ही मालूम था। इसीलिए उसने जो बिल का प्रारूप पेश किया वह महिला आरक्षण तो था ही था बल्कि सरकार की मनसा परिसीमन बिल की अधिक थी। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आई है। 12 वर्ष में सत्ता और विपक्ष में कटुता इतनी बढ़ गई है कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी नहीं होती है।जिस तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और अन्य कांग्रेस नेता आरोप लगा ते रहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाइजैक कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक कांग्रेस ने निष्पक्षता के कटघरे खड़ा कर दिया है।

कांग्रेस का आरोप है कि ED, सीबीआई, NCRTE, NIA, आदि को भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्यों के विधानसभा चुनाव में आयोग की भूमिका को संदेहास्पद मानती है यहां तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला,चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महायोग का नोटिस दिया जा चुका है। अन्य पार्टियां जैसे तुड़मूल कांग्रेस, बीजेडी, सीपीएम, सीपीई, ऋस्क् सपा, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन मानती है। परिसीमन बिल में मुख्य अपत्ति यह थी सरकार कैसे तय कर रही है क्योंकि यह तो चुनाव आयोग या परिसीमन आयोग को निर्णय करना चाहिए वह भी काफी एक्सरसाइज के बाद जबकि बिल में लिखा गया लोकसभा संख्या 850 होगी जिसमें से 35 यूनियन टेरोटरी के लिए आरक्षित होंगी। बिल राज्य बार पचास फीसदी सीट लोकसभा में बढ़ाने का प्रस्ताव था इसी प्रकार राज्यों की विधानसभा सीटों बढ़ेगी। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में 129 के बजाय 195 सीट का प्रस्ताव था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, में 24 फीसदी सीट तय की गई जो वर्तमान से कुछ ही अधिक है। लेकिन विपक्ष की आपत्ति उत्तर प्रदेश में 120, महाराष्ट्र में 78, मध्य प्रदेश में 59,इसी प्रकार राजस्थान, दिल्ली, बिहार, गुजरात, हरियाणा,को लेकर थी।

लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सदन में कह दिया कि हम इस बिल विरोध करेंगे चाहे ह्रष्ठ किसी महिला तो ही प्रधानमंत्री बना दे । राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही यह कह कर भाषण दिया कि महिला आरक्षण तो बहाना है असली बात तो परिसीमन की है। लेकिन प्रस्ताव कोई कमी नहीं थी ।कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं रखे। कांग्रेस और अन्य पार्टियां की पीड़ा है कि अब गिने चुने राज्य रहगये है जहां सरकार अन्य पार्टियां की है जिनमें झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, कर्नाटक, ही है। ये पहला मौका जब विपक्ष एक जुट हुआ है क्योंकि 12 वर्ष में मोदी सरकार ने कभी भी लोकसभा या राज्यसभा में बिल गिरने नहीं दिया है यहां तक कि जम्मू कश्मीर से संविधान की अनुच्छेद 370 पर भी सरकार हारी नहीं थी चाहे वह जीएसटी का मामला हो। 12 वर्ष जिस तरह मोदी सरकार ने कार्य ही नहीं किया बल्कि राज्य विधानसभा चुनाव में दो बार उत्तर प्रदेश,तीन बार बिहार,तीन बार मध्यप्रदेश,दो बार राजस्थान,तीन बार गुजरात,तीन बार हरियाणा,तीन बार उत्तराखंड,दो बार छत्तीसगढ़, ओडिशा,दो बार महाराष्ट्र,सहित 75 चुनाव जीते हैं बस यही कसक कांग्रेस को खाए जा रही है। सपा, डीएमके, तुड़मूल कांग्रेस, बीजेडी, सीपीएम, सीपीई,भी इसी कसक में जले भुजे जा रहे हैं।

क्या शाम होते ही ऊर्जा का स्तर हो जाता है कम? ये हो सकते हैं कारण

आपका दिन किस तरह से बीतता है, यह आपके ऊर्जा के स्तर पर निर्भर करता है। अगर आप शाम होते ही सुस्त और थकान महसूस करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसी आदतें शामिल हैं, जो आपके शरीर और मन को कमजोर कर रही हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो शाम होते ही आपके शरीर और मन को सुस्त कर सकती हैं।

दोपहर का खाना न खाना या इसे छोड़ देना आपकी ऊर्जा को कम कर सकता है। अगर आप दोपहर का खाना नहीं खाते हैं तो शाम को आपको अधिक भूख लगेगी और आप जो भी खाएंगे, उससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। वहीं दोपहर का खाना खाने से आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलती है और आप अधिक सक्रिय रहते हैं। इसलिए, दिनभर में एक बार जरूर भरपेट खाना खाएं। कई लोग दिनभर में कई बार चाय या कॉफी पीते हैं। ये पेय आपको थोड़े समय के लिए ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन इनका अधिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चाय या कॉफी का अधिक सेवन करने से नींद में खलल पड़ सकता है और रात को नींद आने में परेशानी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त इनका अधिक सेवन शरीर के डिहाइड्रेट होने का कारण भी बन सकता है। देर से सोने की आदत भी आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकती है। अगर आप रोजाना देर से सोते हैं तो आपका शरीर ठीक से आराम नहीं कर पाता और अगले दिन आपको थकान महसूस होती है। इसलिए, कोशिश करें कि आप हर दिन एक ही समय पर सोएं और 7 से 8 घंटे की नींद लें, ताकि आपका शरीर ठीक से आराम कर सके और आप अगले दिन तरोताजा महसूस करें। चिंता भी आपके ऊर्जा स्तर को कम करने का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप रोजाना किसी न किसी बात को लेकर चिंता में रहते हैं तो इसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है और आप शाम होते ही सुस्त महसूस करने लग सकते हैं। इसलिए, चिंता को कम करने के लिए रोजाना कुछ मिनट ध्यान या योग करें और अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हों।

राज्यसभा चुनाव : भाजपा के हाथ कानून की तरह लंबे

हर दो साल पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में आम लोगों की तो कम लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी रूचि होती है। कौन उम्मीदवार होगा से लेकर कौन जीतेगा तक सारी चीजें बहुत दिलचस्प होती हैं। सबसे ज्यादा रोचक मामला विधायकों के वोट डालने का होता है। माननीय विधायक इसमें मतदाता होते हैं। यानी जिन लोगों को कई लाख लोग वोट देकर चुनते हैं वे राज्यसभा का सांसद चुनते हैं और सोचें, उनके भी वोट गलत तरीके से डाले जाने की वजह से अवैध हो जाते हैं! क्या यह बात किसी के गले उतरती है कि कोई विधायक ठीक ढंग से वोट नहीं डाल पाएगा? जाहिर है वह जान बूझकर अपना वोट अवैध कराता है। फिर सवाल है कि ऐसे नाटक की क्या जरुरत है? इसमें एक पहलू यह भी है कि राज्यसभा चुनाव में वोट अवैध होने या क्रॉस वोटिंग करने की घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से भाजपा के शक्तिशाली होते जाने के समानुपातिक हैं। यानी जैसे जैसे भाजपा मजबूत हो रही है वैसे वैसे राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा का चुनाव सांस्थायिक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनता जा रहा है।

बहरहाल, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद जो सबसे अपरिहार्य आवश्यकता दिख रही है वह ये है कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के तरीके में बदलाव किया जाए। हर चुनाव में भाजपा जो करती है वह अलग है। उसे तो नहीं रोका जा सकता है। वह तो साम, दाम, दंड और भेद चारों तरीकों का इस्तेमाल करती रहेगी। भाजपा के शक्तिशाली होने के पहले जब कांग्रेस का दौर था, तब भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती थी। लेकिन अब वह गड़बड़ी कई गुना बढ़ गई है।

अगर एक रूपक के हिसाब से कहें तो कांग्रेस के पास ओवरकोट होता था, वह कहीं से एकाध बटन लगाने का बंदोबस्त करती थी। अब भाजपा के पास एक बटन भी होता है तो वह ओवरकोट का इंतजाम कर लेती है। यानी जीतने के लिए 30 वोट की जरुरत है और भाजपा के पास तीन वोट हैं तो वह चुनाव लड़ सकती है और जीत भी सकती है। सो, इसका तो कोई उपाय नही हो सकता है। इसी सचाई के बीच पार्टियों को सर्वाइवल के उपाय करने होंगे।

हां, अगर चुनाव आयोग वोटिंग के नियम भी बदल दे तो कई तरह की नौटकियों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी नौटकियों से जिसकी किसी सभ्य लोकतांत्रिक समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है। वोटिंग के तरीके को सरल बना दिया जाए। इसमें सबसे पहला बदलाव तो यह करने की जरुरत है कि अगर राज्यसभा का चुनाव ओपन बैलेट से होता है और चुनाव में दलबदल का कानून लागू नहीं होता है तो इसे पूरी तरह से ओपन कर देना चाहिए। इस नौटंकी का कोई मतलब नहीं है कि ओपन बैलेट से वोट करेंगे लेकिन वोट सिर्फ अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाएंगे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने देख लिया तो वोट अवैध हो जाएगा। क्यों भाई, दूसरे ने देख लिया तो क्यों अवैध हो जाएगा? जब वह विधायक किसी को भी वोट दे, उसके खिलाफ दलबदल कानून नहीं लागू होना है तो उसका वोट कोई भी देख ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? सोचें, पार्टी के पोलिंग एजेंट को पता है कि उसकी पार्टी का विधायक है तो वह पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेगा। अगर वह पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं करेगा यानी क्रॉस वोटिंग करेगा तब भी पोलिंग एजेंट को उसे अपना वोट दिखाना ही है। वह जिसके पक्ष में क्रॉस वोटिंग करेगा उसको पहले से पता होगा कि क्या होने वाला है।

और क्रॉस वोटिंग के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। फिर भी यह नौटंकी चलती है कि अगर दूसरा व्यक्ति वोट देख लेगा तो वोट अवैध हो जाएगा। इसका सीधा समाधान तो यह है कि राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलेट हो, विधायक बता कर वोट करें कि वे किसको वोट दे रहे हैं और वोट अवैध करने की व्यवस्था ही समाप्त हो। या तो वोट अवैध करने की व्यवस्था समाप्त हो या फिर क्रॉस वोटिंग करने पर दलबदल कानून लागू करने का प्रावधान किया जाए। इससे राज्यसभा चुनाव में होने वाले बेहिसाब भ्रष्टाचार कुछ कम होगा।

इसी तरह की एक नौटंकी यह है कि एक खास तरह के पेन से ही वोट देना होगा। अगर पेन बदल गया या स्याही बदल गई तो वोट अवैध हो जाएगा। हरियाणा में कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ था। जब पेन बदलने से कांग्रेस के 14 में से 13 विधायकों का वोट अवैध हो गया था। इस वजह से इनेलो व कांग्रेस के साझा उम्मीदवार आरके आनंद चुनाव हार गए थे। सवाल है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान होता है और बैलेट पर अपनी प्राथमिकता लिख कर विधायक अपना वोट बक्से में डालते हैं, जो सबके सामने होता है और सबके सामने खुलता है तो फिर उसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, जिसे रोकने के लिए पेन और स्याही की ऐसी व्यवस्था बनाई गई है? पहले ठप्पा लगाने की व्यवस्था थी। उसे बहाल किया जाए और वोटिंग के समय ठप्पा थोड़ा इधर उधर या ऊपर नीचे हो जाने के आधार पर वोट अवैध न किया जाए। सोचें, कैसे कैसे कारण से वोट अवैध हो जाते हैं। इस बार हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में एक विधायक का वोट इसलिए अवैध हो गया क्योंकि उसने पहली प्राथमिकता का वोट देने के लिए अंक में 1 लिखने के बाद उसके आगे डॉट लगा दिया था। ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर पहले भी वोट अवैध होते रहे हैं।

7 भाषाओं में माहिर है साध्वी

फिनाले नाइट में साध्वी का अंदाज देखते ही बन रहा था। उन्होंने सिल्वर और ब्लैक मोनोक्रोम गाउन पहना था, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस और ग्रेस दोनों झलक रहे थे। गाउन का डिजाइन बेहद मॉडर्न था, जिसमें इल्यूजन इफेक्ट के साथ मेटैलिक बीडवर्क किया गया था। उनका ओवरऑल लुक इतना संतुलित था कि जजों की नजरें उन पर टिक गई। उनकी वॉक, एक्सप्रेशन और जवाब देने का तरीका। हर चीज में एक अलग आत्मविश्वास नजर आया।

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2026 के भव्य मंच पर इस बार गोवा की प्रतिभा ने देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साध्वी सतीश सैल ने 30 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज अपने नाम किया। उन्हें मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल ने क्राउन पहनाया। जैसे ही उनके सिर पर क्राउन सजा, पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी और सोशल मीडिया पर उनकी जीत चर्चा का विषय बन गई।

साध्वी सतीश सैल का नाम अब केवल एक ब्यूटी क्वीन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी के तौर पर लिया जा रहा है। उनकी सबसे खास बात यह है कि वे सात अलग-अलग भाषाओं में पढ़, लिख और बातचीत कर सकती हैं। यह क्षमता उन्हें बाकी प्रतियोगियों से अलग बनाती है। उनकी शिक्षा भी उतनी ही मजबूत है। उन्होंने कनाडा की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन्स में डबल मेजर किया है। यह दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ ग्लैमर की दुनिया ही नहीं, बल्कि अकादमिक क्षेत्र में भी खुद को साबित किया है।

30 कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर बनीं मिस इंडिया

फिनाले नाइट में साध्वी का अंदाज देखते ही बन रहा था। उन्होंने सिल्वर और ब्लैक मोनोक्रोम गाउन पहना था, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस और ग्रेस दोनों झलक रहे थे। गाउन का डिजाइन बेहद मॉडर्न था, जिसमें इल्यूजन इफेक्ट के साथ मेटैलिक बीडवर्क किया गया था। उनका ओवरऑल लुक इतना संतुलित था कि जजों की नजरें उन पर टिक गईं। उनकी वॉक, एक्सप्रेशन और जवाब देने का तरीका। हर चीज में एक अलग आत्मविश्वास नजर आया।

साध्वी ने अपने लुक को ज्यादा भारी नहीं बनाया, बल्कि मिनिमल एक्सेसरीज के जरिए अपनी खूबसूरती को उभारा। उन्होंने सिर्फ ड्रॉप इयररिंग्स और एक डायमंड रिंग पहनी, जिससे उनका लुक और भी क्लासी लगा। उनके हेयरस्टाइल में हाफ पिनअप और ओपन हेयर का कॉम्बिनेशन था, जो उन्हें एक एलिगेंट अपील दे रहा था। ग्लॉसी मेकअप के साथ उनका पूरा स्टाइल फिनाले के लिए परफेक्ट साबित हुआ।

कड़ी टक्कर में भी बनाई अपनी अलग पहचान

इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार ने फर्स्ट रनर-अप का खिताब जीता, जबकि जम्मू-कश्मीर की श्री अद्वैता सेकंड रनर-अप रहीं। दोनों ही प्रतियोगियों ने अपने-अपने अंदाज में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन साध्वी की बहुआयामी प्रतिभा और मजबूत पर्सनालिटी ने उन्हें सबसे आगे खड़ा कर दिया।

सोशल मीडिया पर छाई नई ब्यूटी क्वीन

जैसे ही साध्वी सतीश सैल की जीत की खबर सामने आई, उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। उनकी लाइफस्टाइल, एजुकेशन और खासकर उनकी भाषाओं पर पकड़ को लेकर। यही वजह है कि वह सिर्फ एक विनर नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक नई इंस्पिरेशन बनकर उभरी हैं। इस पूरे इवेंट ने यह साबित कर दिया कि आज की ब्यूटी क्वीन सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें टैलेंट, एजुकेशन और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, और साध्वी सतीश सैल इस बदलाव की सबसे मजबूत मिसाल बनकर सामने आई हैं।

ओवरवेट होने के चलते राधिका को एक मूवी से धोना पड़ा था हाथ

राधिका आप्टे की अपकमिंग मूवी मिसेज अंडरकवर 14 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज के लिए तैयार है. इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से राधिका आप्टे अपना जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इसी बीच राधिका ने इस बात का खुलासा किया है कि उनके शुरुआती टाइम में एक्ट्रेस को ओवरवेट की वजह से एक फिल्म से हाथ तक धोना पड़ गया था.राधिका आप्टे ने फिल्म कंपैनियन से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया कि, उन दिनों मेरा वजन तीन से चार किलो ज्यादा था. उन दिनों मुझे अक्सर मेरे जिस्म के कुछ हिस्सों को बदलने के लिए कहा जाता था. तब मुझे एक फिल्म से भी हाथ धोना पड़ गया था. राधिका आप्टे ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा कि, मुझसे कहा जाता था कि तुम्हारी नाक बड़ी क्यों नहीं है और ब्रेस्ट छोटे क्यों हैं. हालांकि अब हम लोग इन सब के बारे में बात कर सकत हैं. उस टाइम हमारे पास सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था और अवेयरनेस की बहुत कमी थी, शायद इसी वजह से उनकी बॉडी का मजाक उड़ाया जाता था.

इन सब बातों के अलावा राधिका आप्टे ने पीटीआई से बात करते हुए %मिसेज अंडरकवर के बारे में भी बताया. एक्ट्रेस ने बताया कि, ये फिल्म जासूसी कॉमेडी के साथ बनी अनएक्सप्लोर्ड जोनरा की मूवी है. मुझे फिल्म के कैरेक्टर %दुर्गा% से बहुत प्यार है, जो कि ईमानदार, मजाकिया और अनाड़ी भी है. इसके साथ वो खुद को लेकर सिन्सेयर नहीं है. ये फिल्म मेरी पावर जर्नी की तरह है.अपनी बात को आगे बताते हुए राधिका आप्टे ने आगे कहा कि, हर घर में एक दुर्गा होती है, जो बस अपना काम करती है और जिसे उसका हक भी नहीं मिलता है. मेरी ये फिल्म सोसायटी की पुरुषवादी सोच से लड़ती हुई नजर आने वाली है।

कृतिका कामरा-विजय वर्मा ने Matka King stream पर ऑन-सेट इक्वेशन पर चर्चा की

लोकप्रिय वेब सीरीज मैटका किंग के सेट पर अभिनेता विजय और अभिनेत्री कृतिका के बीच का सहयोग दर्शकों और आलोचकों दोनों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। हाल ही में दोनों ने एक इंटरव्यू में अपने अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने यह बताया कि उनके ऑन-स्क्रीन प्रदर्शन की सफलता का राज़ टीम वर्क और सहयोग में निहित है।कृतिका ने विजय के अभिनय दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत प्रदर्शन के बजाय सीन की जरूरतों पर अधिक ध्यान देते हैं। उन्होंने बताया, विजय वास्तव में एक तेज अभिनेता हैं और वह खुद के लिए नहीं बल्कि सीन के लिए खेलते हैं। मुझे लगता है कि यह उनके प्रशिक्षण, जिज्ञासा और देने वाले स्वभाव से आता है। कृतिका ने आगे बताया कि इस दृष्टिकोण ने उनके साथ काम करने की प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल बना दिया। दोनों कलाकार बिना अधिक योजना बनाए, सामग्री पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हुए।वहीं विजय ने भी इस दौरान अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि कृतिका अक्सर प्रत्येक टैक के दौरान अपने प्रदर्शन में छोटे-छोटे बदलाव करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सीन हर बार बिल्कुल समान नहीं होते। विजय ने बताया कि इस प्रक्रिया में निरंतर ध्यान और समायोजन की आवश्यकता होती है, जिससे उनका काम अधिक प्रतिक्रियाशील और लचीला बन जाता है, बजाय पहले से तय योजना के।दोनों कलाकारों की टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि मैटका किंग में उनका अभिनय व्यक्तिगत प्रदर्शन से अधिक सीन के सामंजस्य और समयबद्धता पर आधारित है। उनका दृष्टिकोण दर्शाता है कि सहयोगी अभिनय से न केवल दृश्य की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि पूरे सीरीज की कहानी प्रवाह में भी सहजता आती है।इस सहयोगी शैली का एक और पहलू यह है कि दोनों कलाकार अपने अभिनय को स्थिर और सुसंगत बनाए रखने पर जोर देते हैं, जिससे दर्शकों को अनुभव सहज और प्राकृतिक लगता है।

बक्सर में जिला परिषद सदस्यों का अनिश्चितकालीन धरना तेज, करोड़ों की विकास राशि और भुगतान लंबित होने पर प्रशासन घिरा

बक्सर (संवाददाता)। बक्सर जिले में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और लंबित भुगतान को लेकर जिला परिषद सदस्यों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार से जिला परिषद कार्यालय परिसर में सदस्यों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यह धरना दस सूत्री मांगों के समर्थन में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से 15वीं वित्त आयोग और षष्टम राज्य वित्त आयोग की लंबित राशि का भुगतान, पूर्ण हो चुके कार्यों का बकाया निपटान और प्रशासनिक निष्क्रियता पर रोक लगाने की मांग शामिल है।

धरना स्थल पर जिला परिषद सदस्यों ने उप विकास आयुक्त (डीडीसी) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि योजनाओं के लिए स्वीकृत करोड़ों रुपये लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य ठप हो गए हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं पर पड़ रहा है, और जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिषद सदस्य केदार सिंह ने कहा कि वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर जवाब देने में असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डीडीसी की मनमानी और उदासीन रवैये के कारण विकास कार्यों की गति पूरी तरह रुक गई है। उन्होंने बताया कि कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जिससे काम करने वालों में भी नाराजगी बढ़ रही है।

धरना दे रहे सदस्यों का यह भी कहना है कि जिला परिषद की सामान्य बैठकों में लिए गए निर्णयों का समय पर पालन नहीं हो रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी है और प्रशासनिक स्तर पर समन्वय का अभाव साफ दिखाई देता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने पदभार संभालने के कई महीनों बाद भी जिला परिषद कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होकर कार्यों की समीक्षा या निष्पादन नहीं किया।

प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों में पंचम राज्य वित्त आयोग की राशि को विभाग से वापस मंगाने की बात भी प्रमुखता से उठाई है। उनका कहना है कि यदि समय पर फंड उपलब्ध हो जाए और लंबित भुगतान कर दिए जाएं, तो रुके हुए विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकता है।

धरने में शामिल अन्य सदस्यों—राजीव कुमार, नीलम देवी, धर्मेंद्र कुमार ठाकुर, बेबी देवी, गायत्री देवी, ममता कुमारी और सुनैना देवी—ने भी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने एक स्वर में कहा कि यह आंदोलन केवल जनप्रतिनिधियों का नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों की लड़ाई है। धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने भी जिला परिषद सदस्यों का समर्थन किया और कहा कि विकास कार्यों में देरी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सड़क, नाली, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। जिला परिषद सदस्यों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह धरना जारी रहेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि प्रशासन ने जल्द कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

नगर परिषद ने रामरेखा घाट से वीर कुंवर सिंह चौक तक हटवाया अवैध कब्जा

बक्सर (संवाददाता)। नगर परिषद प्रशासन ने शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। अभियान के तहत मंगलवार को नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मियों की टीम हारी पुलिस बल और जेसीबी व ट्रैक्टर के साथ रामरेखा घाट पहुंची। उन्हें देख फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदार और अवैध कब्जेधारियों के बीच हड़कंप मच गया।

रामरेखा घाट पर दुकान लगाने वाले कुछ दुकानदारों ने खुद से सामान समेटने लगे। वहीं कुछ दुकानदारों का दुकान नप के अधिकारियों ने हटवाया। रामरेखा घाट से निकलने के बाद एमपी हाई स्कूल के चहारदीवारी के पास रखें गये गुमटियों को हटाया गया। इस तरह से अभियान के पहले दिन रामरेखा घाट से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक तक फुटपाथ से अवैध कब्जा को हटाया गया।

अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मौके पर मौजूद नगर परिषद के सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि दोबारा फुटपाथ पर दुकान लगाया तो भारी जुर्माना लगाने के साथ सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। वहीं स्थाई दुकानदारों को दायरे के अंदर दुकान लगाने और शेड निकालने की चेतावनी दी। नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तीन दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन दुकानदारों पर एक-एक हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया।

फुटपाथ पर दुकानदारों के कब्जे से हो रही जाम की समस्या : आशुतोष सिंह

नगर परिषद के सफाई निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि शहर में फुटपाथ पर दुकानदारों के कब्जे से हमेशा जाम की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। बुधवार को शहर में रोड या ताड़कानाल से मुनीम चौक तक सख्ती के साथ अवैध कब्जा को हटवाया जाएगा। मौके पर नगर परिषद के नरसिंह चौबे, मो वाहिद अहमद, विजय चौरसिया समेत अन्य कर्मचारियों के अलावा काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद था।

बक्सर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन का कहर, 30 वर्षीय युवक की मौत से गांव में मातम

बक्सर (संवाददाता)। जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। चौसा-मोहनिया मुख्य मार्ग पर निकरिस गांव के पास एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है।

मृतक की पहचान निकरिस गांव निवासी विजय राजभर के रूप में हुई है, जो रामाशंकर राजभर के पुत्र थे। बताया जाता है कि विजय मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे और परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। उनकी अचानक हुई मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विजय किसी आवश्यक काम से घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान चौसा-मोहनिया मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़े। हादसे के तुरंत बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने घायल अवस्था में पड़े विजय को देखा और तुरंत उनके परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और बिना देर किए उन्हें बक्सर सदर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि इलाज के दौरान लगभग 20 मिनट के भीतर ही उनकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही राजपुर थाना की पुलिस हरकत में आई। थानाध्यक्ष निवास कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

वहीं, थानाध्यक्ष निवास कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संभावित सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल, इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने में लगा हुआ है।

सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ी लोगों की चिंता, गति नियंत्रण की मांग

इस घटना ने स्थानीय लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों का आवागमन होता है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर गति नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। समाजसेवी नवीन राय ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मृतक के परिवार को शीघ्र सरकारी मुआवजा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, ताकि इस कठिन समय में उन्हें कुछ राहत मिल सके।

बक्सर में रक्तदान शिविर आयोजित, 16 लोगों ने किया महादान, महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी

बक्सर (संवाददाता)।

समाजसेवा और मानवता की मिसाल पेश करते हुए मारवाड़ी महिला समिति ने 'ब्यूटीफुल लाइफ ऑनली ऑन डोनेटिंग ब्लड' अभियान के तहत एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम ब्लड बक्सर के सहयोग से गोयल अतिथि भवन में आयोजित किया गया, जहां सुबह 11 बजे से रक्तदान की प्रक्रिया शुरू हुई।

शिविर का उद्घाटन रेड क्रॉस के चेयरमैन सुरेश अग्रवाल और महिला समिति की अध्यक्ष लीना गोयल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष सौरभ तिवारी, कोषाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, सचिव श्रवण तिवारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महिला समिति की ओर से सचिव सुनीता केजरीवाल, अंचल प्रमुख ज्योति अग्रवाल, रक्तदान प्रमुख किरण सर्राफ, निशि पोद्दार, उषा गोयल, रुना गोयल, दीपा केजरीवाल और शालिनी सर्राफ सहित अन्य सदस्य भी सक्रिय रूप से शामिल रहीं।

शिविर में कुल 16 लोगों ने रक्तदान कर मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। खास बात यह रही कि इसमें तीन महिलाओं—शालिनी सर्राफ, सुविधा करोटिया और दीपा केजरीवाल—ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे समाज में महिलाओं की जागरूकता और भागीदारी का सकारात्मक संदेश गया। अन्य रक्तदाताओं में राकेश गोयल, सनी गोयल, सुधीर सर्राफ, हर्षित सर्राफ, अभिषेक लोहिया, उज्जवल कुमार, अमजद अली, नीरज मानसिंहका, किशन जायसवाल, आदित्य केजरीवाल, अखिलेश राय, रिजवान अंसारी और लालबाबू पांडेय शामिल रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष लीना गोयल ने कहा कि रक्तदान एक ऐसा महादान है, जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे आगे आकर नियमित रूप से रक्तदान करें और समाज में जागरूकता फैलाएं। वहीं, समिति की सचिव सुनीता केजरीवाल ने रक्तदान के स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इससे शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है तथा शरीर में आयरन का स्तर संतुलित बना रहता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रक्तदान की पूरी प्रक्रिया सुरक्षित होती है और इससे पहले रक्तदाता की आवश्यक स्वास्थ्य जांच नि:शुल्क की जाती है।

बक्सर में सूर्य घर योजना के लिए विशेष कैंप, 34 नए आवेदन प्राप्त, सोलर ऊर्जा के प्रति बढ़ी रुचि

बक्सर (संवाददाता)। बक्सर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने के उद्देश्य से मंगलवार को शहर के गोलंबर क्षेत्र में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में नए आवेदन लेने के साथ-साथ ऋण स्वीकृति (लोन निस्तारण) की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कैंप में पहुंचे और योजना के बारे में जानकारी हासिल की।

कैंप में बिजली विभाग और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही। इस दौरान विद्युत कार्यपालक अभियंता सूर्य प्रकाश सिंह, सहायक विद्युत अभियंता राम लखन राम तथा अग्रणी जिला प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को सोलर ऊर्जा अपनाने के फायदे विस्तार से समझाए और उन्हें अपने घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया। कार्यपालक अभियंता सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से सोलर पैनल लगाने पर आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 1 किलोवाट क्षमता के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम हर महीने लगभग 300 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग शून्य हो सकता है।

कैंप के दौरान कुल 34 नए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि सैकड़ों लोगों ने योजना से जुड़ी जानकारी हासिल की। इसके अलावा दो आवेदकों के लोन का निस्तारण भी मौके पर ही किया गया, जिससे लोगों को त्वरित लाभ मिला। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कैंप का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूक करना और उन्हें आर्थिक रूप से लाभान्वित करना है। सोलर ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे बिजली खर्च में भी काफी कमी आती है।

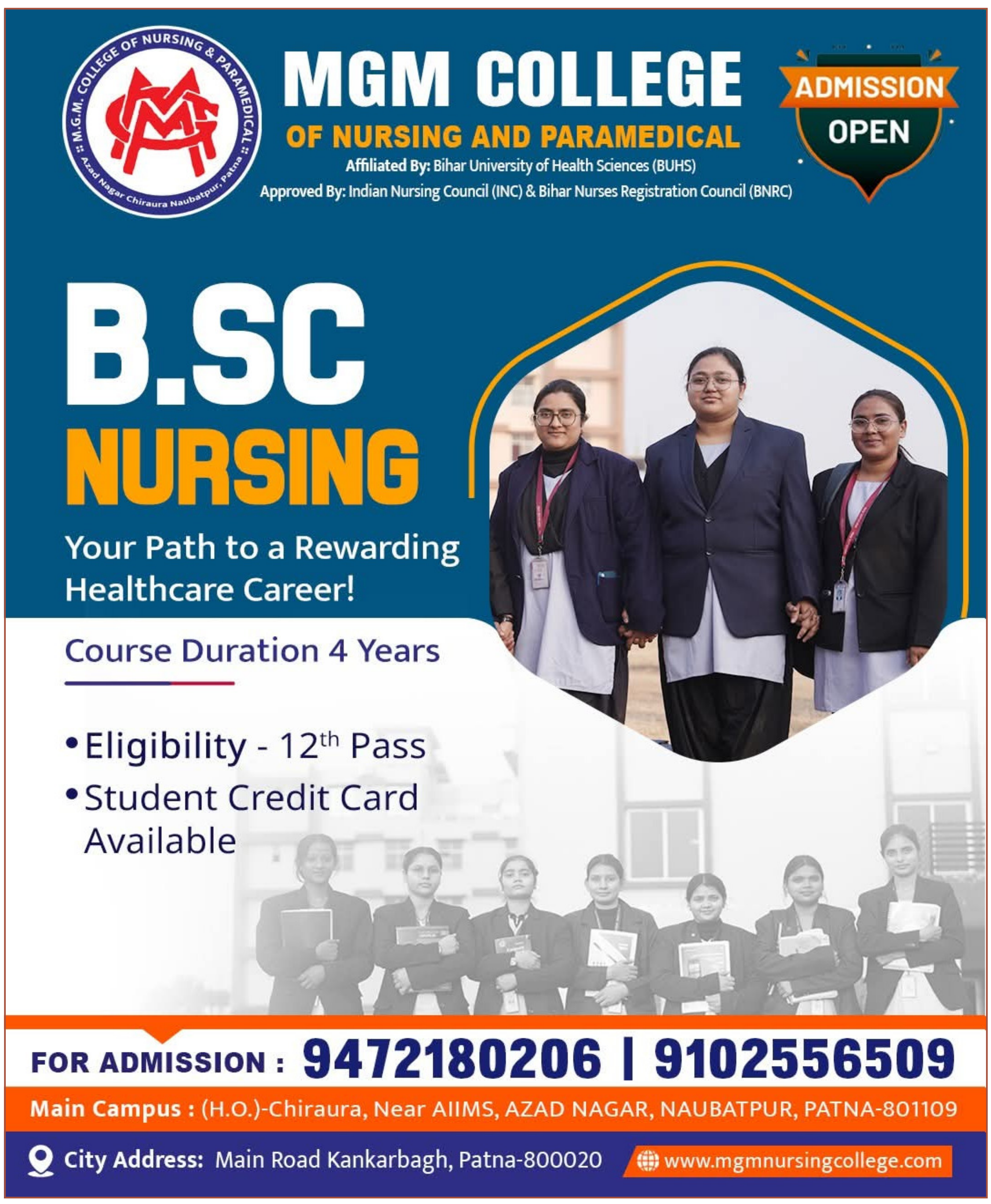

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक मतिउर्रहमान द्वारा अजीमाबाद प्रिंटर्स, आर. सी. एफ./105, ग्राउण्ड फ्लोर, बी. एच. कॉलोनी, भूतनाथ रोड, कंकड़बाग, पटना- 800026 बिहार से मुद्रित एवं अमला टोली, मेन रोड, बक्सर -802101, बिहार से प्रकाशित, संपादक- मतिउर्रहमान, E-mail:- qalamlok@gmail.com, Regn. No. BIHHIN/2017/72480